

बिन शिक्षा सब सून

प्रो.पवन कुमार शर्मा



विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
ए-24-25, सैक्टर-62, नोएडा
उत्तर प्रदेश-201309

पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक-सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय मुक्त
विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार एवं उपयोगिता की संभावनाओं की दृष्टि
से अध्ययन

सर्वेक्षण प्रतिवेदन

मुख्य अन्वेषक

प्रो.पवन कुमार शर्मा

सह अन्वेषक

डॉ. गौरव सिंह

डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी

डॉ. मनोज कुमार ठाकुर



विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, सैक्टर-62, नोएडा

उत्तर प्रदेश-201309

अन्वेषण-मण्डल

<u>क्रम संख्या</u>	<u>नाम</u>
1	प्रो . पवन कुमार शर्मा आचार्य एवं अकादमिक प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
2	डॉ. गौरव सिंह सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली
3	डॉ . प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
4	डॉ . मनोज कुमार ठाकुर अनुसंधान एवं मूल्यांकन अधिकारी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

आभार

अन्वेषण-मण्डल के सभी सदस्य सर्वप्रथम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की शोध परामर्शदात्री समिति को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिसने इतने महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य का उत्तरदायित्व अन्वेषण-मण्डल को सौंपा।

इस सर्वेक्षण कार्य के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के लिए सभी सदस्यों के विश्वविद्यालय के कुलपतिगण/निदेशकगण अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने हेतु सभी सदस्यों को यथासमय अनुमति प्रदान की।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रो. चन्द्रभूषण शर्मा, निदेशक (शैक्षिक) डॉ. कुलदीप अग्रवाल तथा वे समस्त अधिकारी और कर्मचारी हमारे धन्यवाद और आभार के पात्र हैं, जिन्होंने सर्वेक्षण कार्य के सम्पन्न होने तक समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और हमें सहायता प्रदान की।

हम उन सभी सरकारी अधिकारियों, विभिन्न जिलों के नागरिकों और मुख्य रूप से उन बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनकी सहायता के बिना आंकड़ों का संग्रह संभव नहीं था।

अन्वेषण-मण्डल के सभी सदस्य अपने सभी परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी अनुपस्थिति में हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों को सहर्ष स्वीकार कर हमें इस सर्वेक्षण हेतु प्रोत्साहित किया और इस कार्य के पूर्ण होने में सहयोग दिया।

अन्वेषण-मण्डल के सभी सदस्य अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान मार्गदर्शन करने वाले स्थानीय जागरूक नागरिकों विशेष रूप से प्रो. त्रिवेणी सिंह, श्री हिमांशु जी, श्री तुषार जी, श्री रमन जी, श्री पाल जी, श्री काली बाबू, श्री अनुराग शुक्ल, श्री शैलेंद्र जी, श्री शुधांशु जी, श्री अरविंद सिंह, श्री दुर्गेश त्रिपाठी आदि का तथा कठिन मार्गों पर हमारी यात्रा सुलभ करने वाले वाहन चालकों लवकेश, बबलू, यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिनकी सहायता के बिना इस सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण कर पाना असंभव था।

प्राक्कथन

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने जब इस सर्वेक्षण की परिकल्पना की तो इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तरप्रदेश की शैक्षिक स्थिति के उन्नयन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भूमिका को रेखांकित करना था, परन्तु जब अन्वेषण मण्डल ने विभिन्न जिलों में जाकर वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया तो अत्यंत विस्मयकारी स्थितियाँ सामने आयीं। अध्ययन में सम्मिलित आठ जिलों (बलिया, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, अमेठी, फैजाबाद सुल्तानपुर तथा रायबरेली) में कुछ नवोदित जिले थे तो कुछ जिले पुराने थे।

आवश्यक भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से जहाँ बलिया और गोरखपुर समृद्ध जिले प्रतीत हुये, वही अमेठी, अंबेडकरनगर, देवरिया तुलनात्मक रूप से पिछड़े दिखायी दिये। यद्यपि इन तीन जिलों में से दो जिले अमेठी तथा अंबेडकरनगर नवसृजित हैं जो क्रमशः सन 2010 तथा सन 1995 में अस्तित्व में आए, किन्तु ये संसदीय क्षेत्र प्रारम्भ से ही रहे हैं। अमेठी ने तो देश की राजनीति की दृष्टि से भी भारत की संसद में अनेक यशस्वी नेताओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन कर भेजा है, जैसे स्वर्गीय राजीव गाँधी, स्वर्गीय संजय गाँधी, श्रीमती सोनिया गाँधी, कैप्टन सतीश शर्मा, श्री राहुल गाँधी तथा डॉ० संजय सिंह। स्वर्गीय राजीव गाँधी ने तो देश के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का जो द्रुतगामी विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व होने के उपरान्त भी यह क्षेत्र आज भी अपने विकास की बाट जोह रहा है तथा अपने पिछड़ेपन के कारणों को ढूँढ़ रहा है, जो कि समस्त व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है।

यदि शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी परिस्थितियाँ भिन्न नजर नहीं आतीं। इन आठों जिलों में मात्र दो विश्वविद्यालय एक फैजाबाद में तथा एक गोरखपुर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज भी विद्यमान हैं। संपूर्ण देश में सर्वशिक्षा अभियान डेढ़ दशक से चल रहा है और 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' भी विगत कई वर्षों से माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी 2010 से प्रत्येक 8 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन, सर्वेक्षण दल ने जब इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो पाया कि या तो विद्यालय योजना के अनुसार हैं ही नहीं, यदि हैं तो वे बंद हैं या उनकी दशा अवर्णनीय है। उच्च शिक्षा की भी यही दशा है। सर्वाधिक आश्चर्य का विषय यह है कि कुछ स्थानों पर विद्यार्थी मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति के लिए सरकारी विद्यालयों में पंजीकृत तो हैं किन्तु अध्ययन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में पंजीकरण की संख्या में एवं वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या में भिन्नता पायी जाती है क्योंकि एक ही विद्यार्थी दो संस्थाओं में पंजीकृत होता है। सर्वाधिक चिंता का विषय अमेठी का शैक्षिक परिदृश्य है। इस क्षेत्र ने लम्बे समय तक देश की संसद में शीर्ष नेतृत्व को स्थान प्रदत्त किया है फिर भी इस क्षेत्र का शैक्षिक विकास उनकी भावना के अनुरूप परिलक्षित नहीं होता है। बालिकाओं के लिए दू-दू तक विद्यालयों का अभाव दिखता है, वहीं आवागमन के साधन भी ना के बराबर हैं। अमेठी में शिक्षा की स्थिति के विषय में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में रखना पड़ता है। कुछ गाँवों से व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा बालिकाएँ विद्यालय जाती जरूर हैं, लेकिन व्यवस्थित मार्ग के अभाव में उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में आज भी बालिकाओं के द्वारा पशुओं की देखभाल तथा खेती व मज़दूरी सम्बन्धी कार्य करना आम बात है। इस प्रकार के अनेक विषय इस क्षेत्र के विकास पर बड़े प्रश्न खड़ा करते हैं।

इस क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षकों के सम्मुख यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र (देवरिया, अमेठी तथा अम्बेडकर नगर; विशेष रूप से अमेठी) के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए शैक्षिक परिदृश्य एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति जिम्मेदार हैं। विगत कई दशकों के अनुभवों के आधार पर क्षेत्र के नागरिकों से वार्ता करने के उपरान्त यह ध्यान में आया कि इस क्षेत्र का भावनात्मक शोषण ज्यादा हुआ है, चाहे वह राजनेताओं ने किया हो या धार्मिक लोगों ने। जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वह भला आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से दरिद्र कैसे हो सकता है? यद्यपि इस क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रियाशील हैं किन्तु इनकी सक्रियता ने यहाँ की सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्य बदलने में कोई भूमिका निर्वहन नहीं की है; क्योंकि जो सार्वजनिक इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की गयीं उनका संबंध यहाँ के जन और जमीन से कम, राजनीति से अधिक रहा है; इसलिए ना तो यहाँ पर ये इकाइयाँ ही पनप पायीं और ना ही जनता। अन्य जिलों की तुलना अमेठी से करने पर यह स्पष्ट होता है कि अन्य जिलों के विकास में राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रबल हाथ रहा है। उदाहरण के लिए हम बलिया, अमेठी और गोरखपुर की तुलना कर सकते हैं। अमेठी में 11 बार एक ही परिवार से संबंधित व्यक्ति भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करते रहे जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी से संबंधित थे; फिर भी, विकास के सभी आयामों पर यह क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है; वहीं दूसरी ओर गोरखपुर और बलिया का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो भारतीय संसद में लम्बे समय तक तो रहे किन्तु उनके दल शासन का हिस्सा कम समय तक रहे फिर भी उन क्षेत्रों का विकास अमेठी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। इन क्षेत्रों की जनता विकास के दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निर्वहन करती है। सर्वेक्षण के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ कि विकास को लेकर सर्वाधिक प्रश्न इन क्षेत्रों से ही आए। स्वाभाविक ही है कि यदि समाज प्रश्न करता है तो समाधान प्राप्ति का विकल्प उसके पास होता है। लेकिन जो समाज प्रश्न नहीं करता, वह समाधान का कभी हिस्सा भी नहीं होता। अमेठी क्षेत्र की जनता को प्रश्नों के प्रति जागरूक करने में वहाँ का नेतृत्व असफल रहा है इसलिए समाधान भी नहीं बन पाएँ हैं। शिक्षा जो आलोचनात्मक चेतना विकसित करती है तथा मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करती है (सा विद्या या विमुक्तये), उस शिक्षा के अभाव में इस पिछड़े क्षेत्र में ना तो विकास को लेकर नेतृत्व से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और ना ही अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी से मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त हो पा रहा है। यह सर्वेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितनी आबादी (लगभग 2.3 करोड़) का हमने सर्वेक्षण किया है वह भारत की कुल आबादी का लगभग 1.9% है। सर्वाधिक आश्चर्य का विषय यह है कि दुनिया के लगभग 59 देशों की आबादी हमारे सर्वेक्षण की आबादी के बराबर या आस पास है। इनमे से अधिकांश देश अत्यधिक विकसित अवस्था को प्राप्त हैं। यदि शिक्षा पर ठीक प्रकार से ध्यान दिया गया होता तो यह क्षेत्र भी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सकता था।

इस प्रकार की परिस्थितियों में यदि पूर्वी उत्तरप्रदेश और विशेषकर अमेठी, अंबेडकरनगर और देवरिया जैसे जिलों में माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक-सामाजिक परिदृश्य को सुधारना है तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को लीक से हटकर विशेष प्रयास करने होंगे। गाँव-गाँव तक अपनी पहुँच बनानी होगी तथा तकनीकी संसाधनों के माध्यम से बच्चों तक पहुँचना होगा।

नोएडा (ऊ.प्र.)

फरवरी १०, २०१६

अनुक्रमणिका

अनुभाग	पृष्ठ संख्या
1. अध्ययन की पृष्ठभूमि	1
2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व	2
3. समस्या कथन	4
4. अध्ययन के शीर्षक में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएँ	4-6
5. अध्ययन के उद्देश्य	7
6. शोध प्रविधि	8-11
7. अध्ययन की परिसीमाएं	11
8. आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण	11-53
8.1. बलिया	13-18
8.2. देवरिया	19-23
8.3. गोरखपुर	24-28
8.4. सुल्तानपुर	29-33
8.5. अमेठी	34-40
8.6. रायबरेली	41-44
8.7. फैजाबाद	45-48
8.8. अम्बेडकरनगर	49-53
9. अध्ययन के निष्कर्ष	54-61
9.1. जिलों की भौतिक सुविधाओं, शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक चित्रण	54-58
9.2. प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष	59-61
10. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान हेतु सुझाव	62

1.0. अध्ययन की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष के उत्तरी सीमा पर अवस्थित प्रदेश है। इसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगी हुई हैं और यह हिमालय की तराई के कुछ क्षेत्र को भी अपने में समेटे हुए है। हिमालय से निकली हुई अनेक नदियों के संजाल ने इस प्रदेश को कृषि के दृष्टिकोण से समृद्ध किया है। गंगा, यमुना जैसी विशाल नदियाँ तथा इसकी सहायक नदियाँ इस राज्य के विशाल क्षेत्र को अपने जल से न केवल सिंचित करती हैं, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति का भी निर्माण करने में भूमिका निभाती हैं। यह प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो कि विश्व के कई देशों से भी अधिक है। यही कारण है कि इसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संरचना अलग प्रकार से निर्मित हुई है। विश्व में प्रचलित अनेक पंथों के अनुयायी इस प्रदेश में रहते हैं। उनकी सभ्यता का प्रभाव भी इस प्रदेश पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रदेश के इतिहास की पृष्ठभूमि महाकाव्य कालीन है और इसकी छाप यहाँ के निवासियों पर स्पष्ट रूप से दिखती भी है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा जहाँ नेपाल से और उत्तराखण्ड से मिलती है, वहीं इसकी पश्चिमी सीमा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को स्पर्श करती है। इस राज्य के दक्षिण में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ अवस्थित है और पूर्वी दिशा में बिहार है। इस प्रदेश के नागरिकों का संबंध इन प्रदेशों के साथ साथ दूसरे देशों के साथ लम्बे समय से बना हुआ है। मध्य काल से लेकर वर्तमान तक इसने देश की राजनीति एवं सामाजिक दशा को प्रभावित किया है। अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों की प्रारंभिक भूमि होने के नाते यह प्रदेश जाना जाता है। अनेक आयामों के दृष्टिकोण से इस प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है: **पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखण्ड, अवध तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वाञ्चल)।**

यद्यपि इसका कोई राजस्व या प्रशासनिक विभाजन स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी, केवल दो भागों में बाँटते हैं। इन भागों का विभाजन भाषा और भौगोलिक दृष्टिकोण से माना जाता है, लेकिन यह चारों क्षेत्र आपस में अनेक प्रकार से संबद्ध हैं और यही कारण है कि इसका प्रभाव इन क्षेत्रों के विकास आदि पर स्पष्ट रूप से दिखता है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) की शोध परामर्शदात्री समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को समझने के दृष्टिकोण से एक समिति का गठन किया, जिसमें प्रो. पवन कुमार शर्मा, आचार्य एवं अकादमिक प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को प्रमुख अन्वेषक के रूप के नामित करने का निर्णय किया गया। इस निर्णय के आधार पर तीन अन्य सदस्य डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी,

उत्तराखण्ड, तथा डॉ. मनोज कुमार ठाकुर, अनुसंधान एवं मूल्यांकन अधिकारी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सह अन्वेषकों के रूप में नामित किया।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान है। संस्थान को ऐसे वंचित लोगों और स्थानों पर शिक्षा का प्रसार करने और स्कूल न जाने वाले बच्चों और किशोरों को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व दिया गया है, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करता है :

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कार्यक्रम
- लगभग 80 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
- तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के समकक्ष क्रमशः 'ए', 'बी' और 'सी' तीन स्तरों पर मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में एन.आई.ओ.एस. अपनी पाठ्यचर्या और स्व-अनुदेशनात्मक अधिगम सामग्री स्वयं बनाता है तथा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहायक श्रव्य/दृश्य सामग्री तैयार करता है। इसकी अधिगम सामग्री इस ढंग से लिखी गई है कि जो शिक्षार्थियों की गहरी समझ के साथ उनकी समीक्षात्मक सोच तथा सृजनात्मक कल्पना को तीव्रता प्रदान करती है। यह अध्ययन सामग्री शिक्षार्थी के अनुकूल है और शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने में सक्षम बनाती है।

2.0. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

उत्तर प्रदेश एक विशाल जनसंख्या वाला प्रदेश होने के कारण विकास के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप में समृद्ध होते हुए भी एक बीमारू राज्य की श्रेणी में माना जाता रहा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी ताकत, है लेकिन यही इसके लिए कई बार समस्या बन जाती है क्योंकि इस जनसंख्या में अशिक्षा के चलते गरीबी का बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पुराने जिले का संबंध किसी न किसी व्यवसाय के साथ रहा है, इसलिए कृषि के इतर अनेक उद्योग इन जिलों में स्थापित रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद पेशेवर उद्योगों का हास और अशिक्षा में बढ़ोतरी होने के कारण युवाओं का पलायन अन्य राज्यों की ओर हुआ है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विकास सभी क्षेत्रों में समान हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच विकास की स्थिति में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूर्वी उत्तर

प्रदेश में विकास का तुलनात्मक रूप से कम होना, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण है, जिसमें उद्योग धंधों का कम होना, समाज में सामंती व्यवस्था का अभी भी जारी रहना, शिक्षा के अवसरों का कम होना आदि प्रमुख हैं। पूरे देश में पुराने समय से ही शिक्षा की दृष्टि से अनेक संस्थाओं की स्थापना और संचालन समाज द्वारा ही किया जाता रहा है, जिनको बाद में सरकार ने आर्थिक अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं की भी स्थापना हुई, परंतु समय बीतने के साथ इन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर गिरने लगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के नाम पर कुछ निजी विद्यालय भी अस्तित्व में आये, परंतु यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ इनका बहुत प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इन कारणों से न केवल सामाजिक परिदृश्य प्रभावित हुआ बल्कि इसने इस क्षेत्र के शैक्षिक और राजनैतिक परिदृश्य को भी परिवर्तित कर दिया। इसलिए इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था, वह उतना हो न सका।

यह क्षेत्र सामंती दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन जिलों में अनेक देशी रियासतों जैसे अमेठी, सुल्तानपुर आदि का क्षेत्र भी सम्मिलित है इसलिए इन रियासतों की सामंती मानसिकता का प्रभाव भी इस क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में बोलियों के दृष्टिकोण से अवधी और भोजपुरी का प्रयोग होता है। शिक्षा की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में इस क्षेत्र का पिछड़ापन विस्मयकारी है, क्योंकि इस क्षेत्र की बोलियाँ व भाषाएँ हिन्दी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं। इस क्षेत्र ने हिन्दी गद्य और पद्य की दृष्टि से युग प्रवर्तकों को जन्म दिया है। यद्यपि इस क्षेत्र में शासकीय अनुदान प्राप्त अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं लेकिन जनता की आर्थिक और सामाजिक विषमता और अपेक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यल्प है। अतः इस क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही यहाँ की जनता को शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराने का मार्ग खोजा जा सकता है।

यह अध्ययन न केवल इस क्षेत्र की जनता के सामाजिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन सरकारी संस्थाओं के योगदान और भूमिका को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इस क्षेत्र में जन सामान्य के शैक्षिक उन्नयन के लिए क्रियाशील हैं। इस क्षेत्र के दूरे दराज के इलाके जहाँ पर न तो विद्यालय हैं और न ही विद्यार्थी की विद्यालय तक पहुँच है, वहाँ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन के निष्कर्ष मील के पत्थर सिद्ध होंगे।

3.0 समस्या कथन

जैसा कि अध्ययन की प्रस्तावना से स्पष्ट है, इस शोध अध्ययन हेतु विषय का चयन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तार और उपयोगिता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया है। इस कार्य के लिए स्थलीय सर्वेक्षण आधारित अध्ययन को इसीलिए आधार बनाया गया क्योंकि इससे वास्तविक वस्तुस्थिति का पता चल सकता था। उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन को निम्नलिखित रूप से शीर्षकबद्ध किया गया है:

“ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक-सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार एवं उपयोगिता की संभावनाओं की दृष्टि से अध्ययन”

4.0. अध्ययन के शीर्षक में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएँ

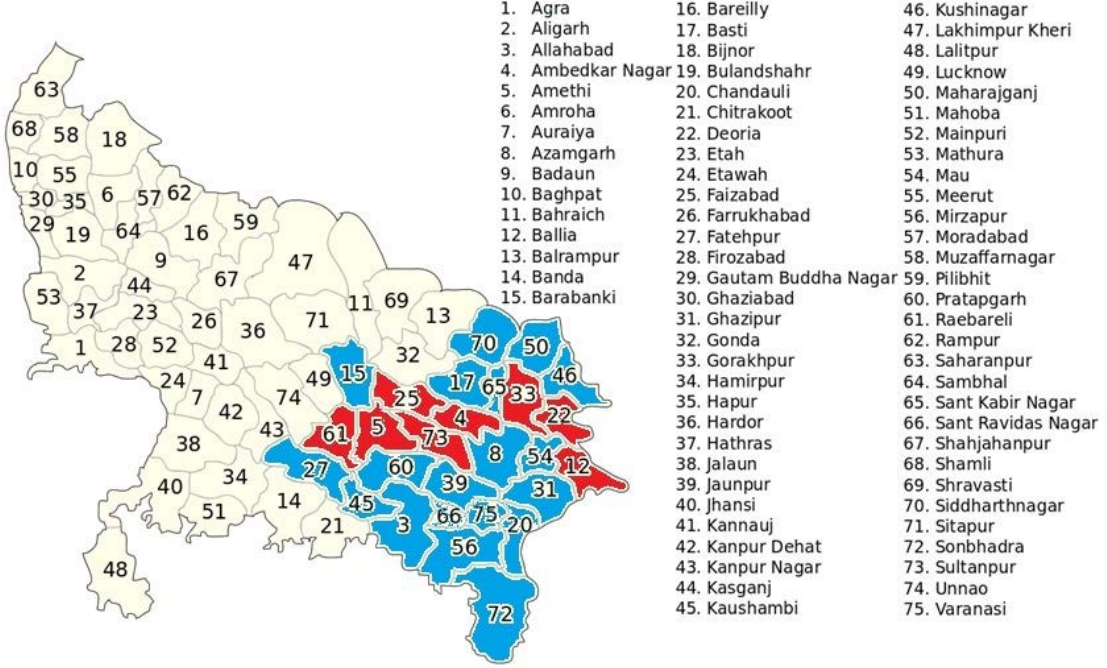
उपर्युक्त अध्ययन के शीर्षक में मुख्यतः जो पद प्रयुक्त हुए हैं, उनकी शोध की दृष्टि से संक्रियात्मक परिभाषाएँ निम्नवत हैं:

4.1 पूर्वी उत्तर प्रदेश

पूर्वी उत्तर प्रदेश से तात्पर्य अविभाजित उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से है, जो मुख्यतः एक ओर बिहार और नेपाल की सीमा से तथा दूसरी ओर बुंदेलखंड की सीमा से लगा है। इसका कोई प्रामाणिक राजस्व या प्रशासनिक अस्तित्व नहीं है। समान्यतः इसके अंतर्गत गोरखपुर (देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर तथा महाराजगंज), वाराणसी (वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर तथा जौनपुर), इलाहाबाद (इलाहाबाद, फ़तेहपुर, कौशांबी तथा प्रतापगढ़), बस्ती (बस्ती, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर), मिर्जापुर (मिर्जापुर, संत रविदासनगर तथा सोनभद्र), आजमगढ़ (आजमगढ़, बलिया तथा मऊ) मंडलों के अंतर्गत आने वाले 21 जिलों के साथ-साथ फ़ैजाबाद मण्डल (अंबेडकरनगर, अमेठी, बाराबंकी, फ़ैजाबाद तथा सुल्तानपुर) के 5 जिले तथा लखनऊ मण्डल के रायबरेली जिले को भी शामिल किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में संक्रियात्मक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश से आशय गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा फ़ैजाबाद मंडलों में आने वाले 26 जिलों तथा लखनऊ मण्डल के रायबरेली जिले से ही है।

Districts of Uttar Pradesh (as of 2012)



परिवर्धित मानचित्र, मूलस्रोत:

[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Uttar_Pradesh#/media/File:List_of_districts_of_Uttar_Pradesh_\(2012\).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Uttar_Pradesh#/media/File:List_of_districts_of_Uttar_Pradesh_(2012).svg)

4.2 ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक-सामाजिक स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक-सामाजिक स्थिति को संक्रियात्मक दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है:

- **जिले की अधो-संरचनात्मक स्थिति:** इसके अंतर्गत मुख्यतः सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगारपरक उद्योग-धंधे आदि को सम्मिलित किया गया है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन:** इस बिन्दु के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, उनके कार्य, घर की स्थिति, गाँव में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय की स्थिति आदि को रखा गया है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति:** इस बिन्दु में गाँव में सामाजिक संघटन, जाति-व्यवस्था, मुख्य रोजगार के साधन, टोलों/पुरवों की संरचना आदि शामिल हैं।
- **शिक्षा के अवसर और शैक्षिक स्थिति:** शिक्षा के अवसर और स्थिति में गाँव के बच्चों के लिए प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता, शैक्षिक संस्थानों की

कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षमता, सामान्य शिक्षा का स्तर, शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा छोड़ने के कारण, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अभिरुचि आदि रखे गए हैं।

4.3 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से तात्पर्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन स्थापित उस स्वायत्त संस्था से है, जिसकी स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से जन-जन तक प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए की गयी है, जिसका मुख्यालय सेक्टर-62, नोएडा में स्थित है और जो पूरे भारतवर्ष में अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है।

4.4 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानके विस्तार एवं उपयोगिता की संभावनाएँ

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार एवं उपयोगिता की संभावनाओं से तात्पर्य उन अवसरों और क्षेत्रों का पता लगाना है, जहाँ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ बनाया जा सकता है और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से 14 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के ग्रामीण बालक-बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत उन युक्तियों की संभावनाएं भी खोजनी हैं जिनके प्रयोग से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकता है।

5.0. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को मुख्य उद्देश्यों तथा द्वितीयक उद्देश्यों के रूप में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

5.1. अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

किसी भी शोध अध्ययन के सुचारु क्रियान्वयन की रूपरेखा उनके उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित होती है। प्रस्तुत शोध की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते समय यह उद्धृत किया गया है कि वर्तमान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा की स्थिति तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन करना है। सर्वेक्षण को अधिक व्यापक तथा तार्किक बनाने हेतु निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए:

1. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु उचित लक्षित समूहों की पहचान करना,
2. लक्षित समूह की शैक्षिक तथा व्यावसायिक अभिरुचियों की पहचान करना,
3. पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) की पहुँच तथा विस्तार के अवसरों की पहचान करना, तथा
4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) के माध्यम से लक्षित समूह की शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यनीति का सुझाव देना।

5.2. अध्ययन के द्वितीयक उद्देश्य

उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों के साथ-साथ अध्ययन के कुछ द्वितीयक उद्देश्य भी निर्धारित किए गए, जिससे मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आधार तैयार हो सके व शोध को कुछ अन्य विशिष्ट लक्ष्यों पर भी केन्द्रित किया जा सके। अध्ययन हेतु निम्नलिखित द्वितीयक उद्देश्य निर्धारित किए गए:

- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ज्ञात करना,
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ज्ञात करना,
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना,

- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं की व्यावसायिक अभिरुचियों की पहचान करना,
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावित विधियोंको ज्ञात करना।

6.0. शोध प्रविधि

6.1 शोध का प्रकार: प्रस्तुत शोध विवरणात्मक प्रकार का शोध (Descriptive Research) है।

6.2 शोध विधि: इस अध्ययन के लिए अवलोकन विधि (Observation Method) तथा सर्वेक्षण विधि (Survey Method) का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान न केवल आधारभूत संरचना एवं भौतिक सुविधाओं का अवलोकन किया गया वरन पूर्व निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर बालक-बालिकाओं के साक्षात्कार के माध्यम से वास्तविक वस्तु-स्थिति समझने का भी प्रयास किया गया।

6.3 शोध का क्षेत्र: पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जिसमें गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा फैजाबाद मंडलों में आने वाले 22 जिले तथा लखनऊ मण्डल का रायबरेली जिला अर्थात कुल 23 जिले आते हैं, प्रस्तुत शोध के क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

6.4 शोध की जनसंख्या: किसी भी शोध की जनसंख्या से तात्पर्य उस जन-समूह से है, जिनके मध्य से शोध के न्यादर्श का चयन किया जाता है। शोध में न्यादर्श के परिणामों का सामान्यीकरण उसी जनसंख्या के लिए किया जाता है। शोध के क्षेत्र में समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश (गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा फैजाबाद मंडलों में आने वाले 22 जिले तथा लखनऊ मण्डल का रायबरेली जिला अर्थात कुल 23 जिले) में रहने वाले 14-19 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाएँ सम्मिलित हैं। रायबरेली जिला लखनऊ मण्डल का अंग है परंतु इसकी कुछ तहसीलों को लेकर एक नए जिले अमेठी का निर्माण किया गया, जिसकी स्थिति अस्पष्ट थी। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संरचना में विकास की विविध योजनाओं का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के माध्यम से होता है, अतः अमेठी में भी जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है उसका क्रियान्वयन अमेठी के जिला बनने से पूर्व रायबरेली तथा सुल्तानपुर जिलों के माध्यम से होता था, इसलिए अमेठी के साथ-साथ दोनों जिलों को जनसंख्या में सम्मिलित करना तर्कसंगत प्रतीत होता है।

6.5 प्रतिदर्शन विधि एवं प्रतिदर्श: प्रस्तुत अध्ययन के लिए बहुचरणीय न्यादर्श चयन पद्धति का प्रयोग किया गया है, जो अग्रलिखित प्रकार से है:

[I] प्रथम चरण: प्रथम चरण में अध्ययन में शामिल 23 जिलों की सूची तैयार की गयी और 8 जिलों का यादृच्छिक चयन किया गया जो निम्नलिखित हैं:-

- i. फ़ैजाबाद
- ii. सुल्तानपुर
- iii. अमेठी
- iv. रायबरेली
- v. अंबेडकर नगर
- vi. गोरखपुर
- vii. बलिया
- viii. देवरिया

[II] द्वितीय चरण: द्वितीय चरण में सभी चयनित जिलों की विभिन्न तहसीलों को सूचीबद्ध किया गया और प्रत्येक जिले से कुछ तहसीलों का यादृच्छिक चयन किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है:

जिला	कुल तहसीलें	चयनित तहसीलें
फ़ैजाबाद	बिकापुर, रुदौली, फ़ैजाबाद, सोहावल, मिल्कीपुर	फ़ैजाबाद (सदर), बिकापुर, मिल्कीपुर
सुल्तानपुर	सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर	सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर
अमेठी	अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, मुसाफिरखाना	अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, मुसाफिरखाना
रायबरेली	रायबरेली, डलमऊ, महाराजगंज, लालगंज, ऊंचाहार, सलोन	रायबरेली, महाराजगंज
अंबेडकर नगर	बिहिटी, टांडा, अकबरपुर, अल्लापुर, जलालपुर	बिहिटी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर
गोरखपुर	गोरखपुर (सदर), चौरीचौरा, सहजनवा, खजनी, कैम्पियरगंज, बांसगाँव, गोला	सहजनवा, कमपियरगंज
बलिया	बैरिया, बलिया, बांसडीह, रसड़ा, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर	बलिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर
देवरिया	बरहज, भाटपाररानी, देवरिया (सदर), रुद्रपुर, सलेमपुर	बरहज, देवरिया (सदर), रुद्रपुर, सलेमपुर

[III] तृतीय चरण: तृतीय चरण में, प्रत्येक चयनित तहसील से **यादृच्छिक चयन** द्वारा 1 या 2 गाँव / पुरवों का चयन किया गया। चयनित गाँव/पुरवों का विवरण निम्नवत है:

जिला	चयनित तहसीलें	चयनित गाँव/पुरवा
फ़ैजाबाद	फ़ैजाबाद (सदर), बिकापुर, मिल्कीपुर	कुसुम्हा, सोनखरी, भवानी, भीखू मिश्रा का पुरवा
सुल्तानपुर	सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर	आरडीह, छेतन का पुरवा, मोहम्मदाबाद, शाहपुर पूरन, कुबेर शाह की पट्टी
अमेठी	अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, मुसाफिरखाना	सटवा, पीढ़ीबहादुरपुर, गुनिया मद्दूफु, बेहटा, पूरे हरपाल सिंह बैस, नारा अधनपुर, छतरी, उखरेंमऊ, खदे का पुरवा, जानापुर
रायबरेली	रायबरेली, महाराजगंज	पहाड़ाखेरा, सोहरा, नया पुरवा, अमरावां
अंबेडकर नगर	बिहिटी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर	अरई, रोशनपुर मजरा, केवटही, ब्राहिनपुर, कुसुमा सागरा
गोरखपुर	सहजनवा, कमपियरगंज	जगरनाथपुर, ककना, चकपट्टा
बलिया	बलिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर	मुजौना, माधोपुर, गोसाईपुर, देवडीह, केवटिया
देवरिया	बरहज, देवरिया (सदर), रुद्रपुर, सलेमपुर	जमुआ, सुसबहा, चौरडीह, बनसईयां

[IV] चतुर्थ चरण: प्रत्येक चयनित गाँव में आकस्मिक प्रतिदर्श चयन विधि का प्रयोग करते हुये उपलब्ध ऐसे बालक-बालिकाओं से मिलकर उनका साक्षात्कार लिया गया, जो 14-19 आयु वर्ग के हों। चयनित बच्चों की संख्या और लिंगवार उनका क्विरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

क्रम संख्या	जिला	तहसील	गाँव/पुरवा	बच्चे	
				बालक	बालिका
1.	फ़ैजाबाद	फ़ैजाबाद (सदर), बिकापुर, मिल्कीपुर	कुसुम्हा, सोनखरी, भवानी, भीखू मिश्रा का पुरवा	20	40
2.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर	आरडीह, छेतन का पुरवा, मोहम्मदाबाद, शाहपुर पूरन, कुबेर शाह की पट्टी	17	43

3.	अमेठी	अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, मुसाफिरखाना	सटवा, पीढ़ीबहादुरपुर, गुनिया महूपुर, बेहटा, पूरे हरपाल सिंह बैस, नारा अधनपुर, छतरी, उखेरेमऊ, खदे का पुरवा, जानापुर	18	42
4.	रायबरेली	रायबरेली, महाराजगंज	पहाड़ाखेरा, सोहरा, नया पुरवा, अमरावां	06	54
5.	अंबेडकर नगर	बिहिटी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर	अरई, रोशनपुर मजरा, केवटही, ब्राह्मिनपुर, कुसुमा सागरा	09	51
6.	गोरखपुर	सहजनवा, कमपियरगंज	जगरनाथपुर, ककना, चकपट्टा,	20	40
7.	बलिया	बलिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर	मुजौना, माधोपुर, गोसाईपुर, देवडीह, केवटिया	11	49
8.	देवरिया	बरहज, देवरिया (सदर), रुद्रपुर, सलेमपुर	जमुआ, सुसबहा, चौरडीह, बनसईयां	27	33

अतः कुल मिलाकर 128 बालक और 352 बालिकाएँ इस शोध में सम्मिलित किए गए।

6.6 शोध हेतु उपकरण:

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शोध उपकरणों का प्रयोग किया गया:

6.6.1 अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग बालक-बालिकाओं के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, परिवार में सदस्यों की संख्या, शिक्षा स्तर, शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों, अभिरुचि आदि बिन्दुओं पर जानकारी एकत्र करने हेतु किया गया।

6.6.2 अवलोकन अनुसूची: अवलोकन अनुसूची का प्रयोग गाँव की स्थिति, गाँव का सामाजिक ताना-बाना, परिवार का रहन-सहन, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षा के अवसर आदि के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने हेतु किया गया।

6.7 विश्लेषण विधि: प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिशत विश्लेषण एवं अन्य गुणात्मक विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया।

7.0. अध्ययन की परिसीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन को चुने हुए 8 जिलों के ग्रामीण/सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 14-19 वर्ष के बालक-बालिकाओं व उनके अभिभावकों तक ही परिसीमित किया गया।

8.0. आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में जिले की प्राथमिक सूचना तथा अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से आंकड़ों को निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में संग्रहीत किया गया:

जिलावार ब्योरा:

1. जिले का सामान्य परिचय: अस्तित्व (कब से), स्थिति (कहाँ पर स्थित है, मंडल, तहसील, विकासखंड आदि) एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े, शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े, शैक्षिक संस्थानों की संख्या, शिक्षकों व विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अनुपात, प्रमुख व्यवसाय, कृषि की स्थिति, ग्रामीण व शहरी जनता की स्थिति, जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के केन्द्रों की स्थिति।
2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए।
3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति
4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ तथा उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति।
5. जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव।

अध्ययन के दौरान उपर्युक्त बिन्दुओं के अंतर्गत सूचनाएँ एकत्र की गयीं, जिसे यहाँ जिलावार प्रस्तुत किया जा रहा है-

8.1. बलिया जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

बलिया उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में आता है तथा जिसकी सीमाएँ बिहार राज्य

से लगती हैं। यह जिला

आजमगढ़ मंडल के अन्तर्गत

आता है। इस जिले के अन्तर्गत

बैरिया, बलिया, बांसडीह,

रसड़ा, बेलथरा रोड तथा

सिकंदरपुर नाम की कुल 6

तहसीलें हैं। उपर्युक्त तहसीलों



के अन्तर्गत विकासखंडों की कुल संख्या 15 है।

यह मुख्यतः गंगा और घाघरानदियों के मध्य स्थित है, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। 2011 की

जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 3,223,642 है, जिसमें 1,667,557 पुरुष तथा 1,556,085

महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत

साक्षरता 73.82 % है, जबकि पुरुष साक्षरता 85.91 % तथा स्त्री साक्षरता मात्र 61.72 % ही है। जिले में कुल

3841 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 02 प्रत्यायित संस्था

(AIs) तथा 02 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

बलिया जिले में बैरिया, बलिया, बांसडीह, रसड़ा, बेलथरा रोड तथा सिकंदरपुर नाम की कुल 6 तहसीलें हैं, जिनमें

से इस अध्ययन में बलिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर के रूप में चार तहसीलों के मुजौना, माधोपुर,

गोसाईपुर, देवडीह तथा केवटिया नामक पाँच गाँवों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में

अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 30 पुरुषों व 20 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार

अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 11 बालकों व 49 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:

बलिया जिले के भ्रमण के दौरान ये देखने में आया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति तुलनात्मक रूप से ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यमार्गों की



स्थिति संतोषजनक है; साथ ही अधिकांश गाँव भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जुड़े हैं परन्तु नदी (घाघरा) के आस पास के कुछ गाँवों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सभी गाँवों में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं।

कुछ गाँवों में पेयजल की सुविधा हेतु पानी की टंकी भी लगी है किन्तु बिजली की आपूर्ति में समस्या है। गाँव व पुरवों में अधकच्चे मकान भी दिखे परन्तु पक्के मकानों की संख्या भी ठीक-ठाक थी। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश गाँवों में 1-2 कि.मी. के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्थित है। जिला बलिया में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज उचित संख्या में हैं और सभी वर्गों के लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता है।

ii. शैक्षिक स्थिति:

2014-15 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बलिया में 3841 प्राथमिक तथा प्रारम्भिक विद्यालय हैं, जिनमें से 11 बिना शिक्षक के, 209 एक शिक्षक



वाले तथा 293 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 513 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। 217 विद्यालयों में एक भी शौचालय नहीं हैं, जबकि 690 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2392 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, जो कि वर्तमान में तकनीकी समर्थित शिक्षा के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है।

उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ अन्य तथ्य भी स्पष्ट होते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

- विद्यालयों की संख्या तो पर्याप्त है परंतु बहुत से विद्यालयों में अभी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

- 500 से अधिक सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाना अकल्पनीय है।



यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु वहाँ के निवासियों के अनुसार सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय मात्र परीक्षा केंद्र के रूप में चलते हैं, वहाँ रोजमर्रा की पढ़ाई नहीं होती और

अक्सर दिन में 12 बजे भी वहाँ ताले लटकते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं, परंतु वहाँ शुल्क अधिक होने के कारण गरीब बच्चे 8वीं के बाद की पढ़ाई छोड़ देते हैं।



- आम जनता सरकारी शिक्षा व्यवस्था से घोर निराशा में है। एक ग्रामीण के शब्दों में “सरकारी स्कूल में मास्टर और बच्चे खाना खाये के वास्ते जात हैं, बस; कौन पढ़ाई लिखाई ना होत है”। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में नियमानुसार वास्तविक रूप से अध्ययन-अध्यापन होता होगा, इसमें संशय है।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:

जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया, वहाँ सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। अंबेडकर गांवों जहाँ सरकार ने शौचालय बनवाकर दिये, वहाँ भी शौचालय अधिकतर प्रयोग में नहीं आते हैं। इसके कई तकनीकी कारण देखने में आए जैसे गड्डे का छोटा होना, पानी की व्यवस्था का न होना, आदि। लोगों में शौचालयों के प्रति जागरूकता कम पायी गयी।

गाँवों में कुछ जातियाँ राजपूत समुदाय के लोगों को 'बाबू साहब' जैसे सम्बोधन से पुकारती हैं, जो कि परंपरागत है। कुछ लोगों के दरवाजे पर पुराने कुएँ देखे गए, जो प्रायः प्रचलन में नहीं हैं। गाँवों में परम्परागत रूप से जाति के आधार पर

पुरवों/ टोलों की उपस्थिति देखी गयी। एक ग्रामीण ने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ वर्चस्व वाले लोगों को ही मिलता है क्योंकि सरकारी



कर्मचारी और अधिकारी यदि गाँव में आते हैं तो वे भी उन्हीं के घर बैठते हैं और गाँव के अन्य लोगों को उनके आने का पता भी नहीं चल पाता। सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि इस जिले में गरीबी उन क्षेत्रों में ज्यादा है, जो या तो नदी किनारे के गाँव हैं या जिनमें अनुसूचित जाति का बाहुल्य है। जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया, वहाँ कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के घर पाये गये। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं परंतु कई जगह कुएँ भी खुदे हुए हैं और लोग इनका पानी पीते हैं। वहाँ के निवासियों के अनुसार इन क्षेत्रों में बिजली औसतन 2-5 घंटे ही रहती है। अधिकांश लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं।

जो बहुत गरीब एवं अनपढ़ हैं वे भी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, किन्तु यह भी पाया गया कि अधिकांश संख्या में घरों में टीवी नहीं है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो यह पाया गया कि लड़कियाँ अब गाँवों में भी पढ़ रहीं हैं। अभिभावक अब लड़कियों के लिए भी जागरूक हो गये हैं परंतु वरीयता अब भी लड़कों के लिए दृष्टिगोचर होती है। गाँवों की लगभग सभी लड़कियाँ 8वीं-10वीं तक तो पढ़ लेती हैं, लेकिन

इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनके गांव के आस पास कोई अच्छा इंटर कॉलेज और डिग्रीकॉलेज नहीं है।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयी रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति वजिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 18.33% लड़के तथा 81.66% लड़कियाँ हैं। आकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि 50 % बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं, जबकि मात्र 10 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं। केवल 10 % बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में पाये गए, शेष की अपनी दुकान या स्व-रोजगार है। 87.5 % बच्चे दो से अधिक भाई-बहन वाले हैं और 53.13 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है।

18.75 % बच्चों ने कक्षा 8 तक तथा 43.75 % बच्चों ने 10 या 12 तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि 100 % बच्चे अवसर



मिलने पर आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार की यहाँ कितनी संभावनाएँ हैं। 90.63 % बच्चों ने यह बताया कि उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं, जबकि मात्र 9.37 % बच्चों ने स्व-रोजगारपरक शिक्षा को उपयोगी माना। उपर्युक्त बिंदुओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि:
 - ज्यादातर बच्चों ने एक से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में रुचि व्यक्त की। 53.13% बालिकाओं की सिलाई और कढ़ाई, 40.63 % बालिकाओं की ब्यूटीशियन, 21.87 % बालक-बालिकाओं की

कम्प्यूटर या इलेक्ट्रिशियन सम्बन्धी कार्यक्रम में रुचि देखी गयी। इसके साथ ही कुछ बच्चों ने मेडिकल संबंधी क्षेत्रों और मोबाइल रिपेयरिंग सम्बन्धी कार्यों में भी अपनी रुचि व्यक्त की।

- इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानको इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.2. देवरिया जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

देवरिया उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में आता है तथा इसकी सीमाएँ बिहार राज्य से लगती हैं। जिले का मुख्यालय देवरिया सदर है। यह जिला गोरखपुर मंडल के अन्तर्गत आता है। इस जिले के अन्तर्गत बरहज, भाटपाररानी, देवरिया (सदर), रुद्रपुर तथा सलेमपुर नाम की कुल 5 तहसीलें आती हैं। उपर्युक्त तहसीलों के अन्तर्गत विकासखण्डों की कुल संख्या 16 है। इस जिले में मुख्यतः राप्ती और घाघरा नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है।

2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 30,98,637 है, जिसमें 15,39,608 पुरुष तथा 15,59,029 महिलाएँ हैं। वर्तमान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1013 स्त्रियाँ है। यहाँ



की औसत साक्षरता 73.53 % है, जिसमें पुरुष साक्षरता 86.07 % तथा स्त्री साक्षरता मात्र 61.34 % ही है। जिले में कुल 3957 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 02 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 01 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

देवरिया जिले में बरहज, भाटपाररानी, देवरिया (सदर), रुद्रपुर तथा सलेमपुर नाम की कुल 5 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में बरहज, देवरिया (सदर), रुद्रपुर तथा सलेमपुर के रूप में चार तहसीलों के जमुआ, सुसबहा, चौरडीह, बनसईयां नामक चार गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 28 पुरुषों व 22 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 27 बालकों व 33 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:

देवरिया जिला के अधिकतर गांवों की सड़कें और गांवों से जुड़ी मुख्य सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जिले से गुजरने वाले राजमार्ग की हालत लगभग ठीक है। देवरिया, गोरखपुर और बलिया की तुलना में पिछड़ा है और इस जिले के गांवों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। गांवों में पेयजल हैंडपम्प के माध्यम से प्राप्त होता है; कुछ जगहों पर पुराने कुएँ भी देखे गए। गांवों में लगभग 5-6 घंटे ही बिजली रहती है। मकानों की स्थिति भी कच्ची-पक्की देखने में आयी।



ii. शैक्षिक स्थिति: 2014-15 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 3957 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 25 बिना शिक्षक के, 238 एक शिक्षक वाले तथा 614 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस



प्रकार कुल 877 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2312 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन नहीं है।

उपयुक्त आंकड़ों से कुछ तथ्य जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं वे निम्नलिखित हैं:-

- बहुत से सरकारी विद्यालयों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसका लाभ दोगुम प्रकार के निजी विद्यालय उठा रहे हैं।
- 877 से अधिक सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर प्रश्न खड़ा होता है। यद्यपि, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है किन्तु अध्ययन के दृष्टिकोण से उन विद्यालयों की स्थिति थोड़ी कमजोर प्रतीत होती है, ऐसे में ये विद्यालय मात्र परीक्षा संचालन उपक्रम बन कर रह गए हैं।
- ग्रामीणों का यह कहना है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने विद्यालयों को मात्र खाने के स्थान के रूप में



स्थापित कर दिया है, जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं व मौज-मस्ती करते हैं। अगली कक्षा में मास्टर साहब उनको ऐसे ही भेज देते हैं। सम्पन्न परिवारों के बच्चे गाँवों से 10-15 किलोमीटर की दूरी तक भी अपने साधनों से

निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:

जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया वहां सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग अभी भी खुले क्षेत्र में ही शौच के लिए जाते हैं। कुछ लोगों ने खुले में शौच जाने की वकालत की लेकिन महिलाओं ने बरसात के दिनों में, जाड़ों में एवं रात में बाहर जाना असुविधाजनक माना।



जिन गाँवों को पूर्व में अंबेडकर गांव का दर्जा मिला हुआ था, उन गाँवों की स्थिति थोड़ी साफ-सुथरी दिखी किन्तु रख-रखाव के अभाव में सड़क, नाली एवं शौचालयों की स्थिति बदतर हो गयी है। गाँवों में गरीबी सर्वत्र

परिलक्षित होती है, इसी गरीबी में कुछ बालक अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु जदोजहद करते दिखे इन गाँवों में से कुछ अभिभावक जो बाहर नौकरी करते हैं, उन परिवार के बच्चों की समझदारी अन्य बच्चों की



तुलना में ज्यादा दिखी। उनके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण भी अन्य बच्चों की तुलना में भिन्न था। गाँवों में कच्चे-पक्के मकान दिखे किन्तु जागरूकता के कारण साफ-सुथरे थे।

गाँवों में बिजली कम समय ही रहती है।

गाँवों में सामाजिक ताना-बाना आज भी पारम्परिक दृष्टिकोण का ही है किन्तु जागरूकता बढ़ी है। गाँवों में अधिकांश लोगों के पास मोबाइल फोन है। परंतु यह भी पाया गया कि अधिकांश घरों में टीवी नहीं है। देवरिया जिले में भी यह देखा गया कि लड़कियां घर के काम के अतिरिक्त गाय बकरी चराना, खेतों में काम करना आदि काम भी करती हैं।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव:

- सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष हैं, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 45% लड़के तथा 55% लड़कियां हैं।
- 42% बच्चों के माता-पिता मज़दूरी करते हैं, जबकि 37% बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं। केवल 21% बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी वाले मिले।
- सभी बच्चों के एक से अधिक भाई-बहन पाए गए और 42% परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा मिली।

- 46% बच्चों ने कक्षा 8 के बाद, 42 % बच्चों ने 10 या 12 तक और 12% बच्चों ने कक्षा 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी बच्चे, जो अभी तक नहीं पढ़ सके हैं वे अवसर मिलने पर पुनः पढ़ने के इच्छुक हैं। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानके विस्तार की संभावनाएं प्रबल हैं। बच्चों ने बताया कि उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं अर्थात इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की वह शिक्षा अधिक उपयोगी होगी, जो रोजगारपरक है।



- 4% बच्चों ने माता-पिता के शुल्क न देने की क्षमता को अपनी पढ़ाई छोड़ने का कारण बताया।
- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है

कि 42% बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं सिलाई-कढ़ाई कार्य, 21% बच्चों की प्राथमिकता ब्युटिशियन सम्बन्धी कार्य, 33% बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण, 12% बच्चों की प्राथमिकता इलेक्ट्रिशियन सम्बन्धी कार्य, 8% बच्चों की प्राथमिकता ऑटो मैकेनिक सम्बन्धी कार्य तथा 4% बच्चों की प्राथमिकता प्लम्बर का काम सीखने की है।

- इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर लिखे विषय महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता है।

8.3. गोरखपुर जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

गोरखपुर उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जिलों में से एक है जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। जिले का मुख्यालय गोरखपुर है, जो मंडल का भी मुख्यालय है गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ के नाम से सुविख्यात है और साथ ही यह अनेक पुरातात्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को समेटे हुए है। यह मुंशी प्रेमचन्द की कर्मस्थली व फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह अमर शहीद पं० राम प्रसाद बिस्मिल व चौरीचौरा आन्दोलन के शहीदों की शहादत स्थली रही है। गोरखपुर हस्तकला 'टैराकोटा' के लिए भी प्रसिद्ध है। गोरखपुर जिला महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ तथा संत कबीर नगर जिलों से सटा हुआ है। इस जिले के अन्तर्गत गोरखपुर (सदर), चौरीचौरा, सहजनवा, खजनी, कैम्पियरगंज, बांसगाँव तथा गोला नाम की कुल 7 तहसीलें आती हैं। उपर्युक्त तहसीलों के अन्तर्गत विकासखंडों की कुल संख्या 12 है। इस जिले में मुख्यतः राप्ती और रोहिणी नदियाँ बहती हैं। इस जिले की सीमा नेपाल से सटी हुई है, जिसके कारण यह अधिक संवेदनशील जिला माना जाता है। तराई क्षेत्र होने के कारण इसमें वन क्षेत्र भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 44,36,275 है, जिसमें 22,81,763 पुरुष तथा 21,54,512 महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 944 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत साक्षरता 73.25 % है, जबकि पुरुष साक्षरता 84.38 % तथा स्त्री साक्षरता मात्र 61.54 % ही है। जिले में कुल 4521 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ की 18.83 % जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में, जबकि 81.17 % जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 02 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 05 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

गोरखपुर जिले में गोरखपुर (सदर), चौरीचौरा, सहजनवा, खजनी, कैम्पियरगंज, बांसगाँव तथा गोला नाम की कुल 7 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में सहजनवा तथा कैम्पियरगंज के रूप में दो तहसीलों के जगरनाथपुर, ककना तथा चकपट्टा नामक तीन गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 32 पुरुषों व 18 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 20 बालकों व 40 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:

गोरखपुर जिले के भ्रमण के दौरान ये देखने में आया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति आस



पास के जिलों की तुलना में ठीक-ठाक है। राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य मार्गों की स्थिति संतोषजनक है और साथ ही अधिकांश गाँव भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जुड़े हैं। यद्यपि राप्ती के आस पास के गाँव में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की थोड़ी कमी है। कुछ गाँवों में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश गाँवों में प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल स्थित हैं। जिला गोरखपुर में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज उचित संख्या में है और लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता है। इन सब परिस्थितियों के निर्माण में इस जिले का प्राचीन होना भी एक कारण है।



ii. शैक्षिक स्थिति:

सरकारी आंकड़ों के अनुसार (2014-15) गोरखपुर में 4521 विद्यालय हैं, जिनमें से 1 बिना शिक्षक के, 189 एक शिक्षक वाले तथा 509 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 699 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। 1597 विद्यालय बिना प्रधानाचार्य के हैं। 27 विद्यालय एक कक्ष वाले हैं, जबकि 49 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं हैं। 33 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि 1597 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, जो कि आज के समय में एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से तो गोरखपुर में पर्याप्त विद्यालय हैं परंतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जिले में यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय में रोजमर्रा की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती इसलिए बहुत से बच्चे निजी-विद्यालयों में जाते हैं, परंतु वहाँ शुल्क अधिक होने के कारण अधिकांश गरीब बच्चे पढ़ाई



बीच में छोड़ देते हैं।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:

गाँवों के सर्वेक्षण के दौरान यह ध्यान में आया कि पुराना जिला होने के उपरान्त भी ग्रामीण जनता थोड़ी प्रगतिशील सोच रखती है लेकिन कुछ बातों में वे आज भी परंपरागत दृष्टिकोण को प्रधानता देते हैं, जैसे-

शौचालय का मुद्दा उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका संपर्क संबंध शहरों के सभ्य स्थापित हो चुका है किन्तु यह महत्वपूर्ण मुद्दा सर्वत्र क्रियाशील नहीं है इसलिए शौचालय की स्थिति यहाँ वैसी ही है जैसी कि अन्य जिलों में।

शौचालय न बनाने के कुछ प्रमुख कारण अर्थाभाव, पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होना तथा रूढ़िवादी मानसिकता आदि हैं। गाँवों के मकानों की स्थिति मिलीजुली है। बाढ़ के प्रकोप से भी यह जिला यदा-कदा त्रस्त रहता है, इस कारण भी नदियों के तट पर स्थित गाँवों की स्थिति ठीक नहीं है। पेयजल के लिए हैंडपम्प का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, कुछ स्थान पर कुएँ भी मिले। गाँवों में बिजली तकरीबन 7-8 घंटे रहती है।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

- सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 33.33 % लड़के तथा 66.66% लड़कियाँ हैं।



- 55 % बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं, 35 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं तथा 10% बच्चों के माता-पिता की अपनी दुकान या स्व-रोजगार है।
- 95 % बच्चे दो से अधिक भाई-बहन हैं और 55 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है।
- 20 % बच्चों ने कक्षा 8 तक तथा 80 % बच्चों ने कक्षा



10 या 12 तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि 100 % बच्चे अवसर मिलने पर आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानके विस्तार की वहाँ कितनी संभावनाएं हैं।

- 35% बच्चों ने बताया की उनके परिवार से उन्हें पढ़ने के लिए मदद नहीं मिल सकती इसलिए वे आगे नहीं पढ़ सकते हैं परंतु यदि उन्हें मदद मिले तो वे आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिससे वे पढ़ाई करके नौकरी कर सकें। लगभग 95% बच्चे पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक हैं परंतु वे चाहते हैं कि उन्हें वह शिक्षा दी जाए जो स्व-रोजगारपरक हो।
- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो वह स्पष्ट होता है कि 85% बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं सिलाई और कढ़ाई, 25 % बच्चों के प्राथमिकता ब्यूटीशियन, 10 % बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर या इलेक्ट्रिशियन का कार्य है। इसके साथ ही कुछ बच्चों ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कार्यों तथा मोबाइल रिपेयरिंग में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की।
- इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानको इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.4. सुल्तानपुर जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक है, जो अवध क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। यह जिला फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत आता है। इस जिले के अन्तर्गत सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर नाम की कुल 6 तहसीलें आती हैं। उपर्युक्त तहसीलों के अन्तर्गत विकासखंडों की कुल संख्या 13 हैं। इस जिले से गोमती नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ की



भूमि अत्यंत उपजाऊ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 37,90,922 है, जिसमें 19,16,297 पुरुष तथा 18,74,625 महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 978 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत साक्षरता 71.14% है, जबकि पुरुष साक्षरता 81.99 % तथा स्त्री साक्षरता मात्र 60.17% ही है। जिले में कुल 3467 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 03 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 03 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।



2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

सुल्तानपुर जिले में सुल्तानपुर (सदर), कादीपुर, लम्भुआ तथा जयसिंहपुर नाम की कुल 4 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में सभी चारों तहसीलों के आरडीह, छेतन का पुरवा, मोहम्मदाबाद, शाहपुर पूरन तथा कुबेर शाह की पट्टी नामक 5 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 20 पुरुषों व 30 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 17 बालकों व 43 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति: जिला सुल्तानपुर के अधिकतर गांवों में और गांवों से जुड़ी सड़कों की स्थिति लगभग ठीक है। जिले से गुजरने वाले राजमार्ग की हालत भी ठीक है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि गाँवों में 1 कि. मी. के क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय स्थित है। परंतु अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कम है। कई विद्यालयों में केवल एक या दो ही अध्यापक हैं। इन विद्यालयों की स्थिति भी चिन्ताजनक है। अन्य जिलों भाँति सुल्तानपुर में भी माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज कम हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की इन माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेज तक पहुँच कम है।

ii. शैक्षिक स्थिति: सरकारी आंकड़ों के अनुसार (2014-15) सुल्तानपुर में 3467 विद्यालय हैं, जिनमें से 10 बिना शिक्षक के, 252 एक शिक्षक वाले तथा 672 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 934 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। 390 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय



नहीं हैं। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2072 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, जिससे तकनीकी समर्थित शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ तथ्य जो स्पष्ट होते हैं वह इस प्रकार हैं:

- विद्यालयों की संख्या की तुलना में यहाँ अभी भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- 934 से अधिक सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त तो नहीं ही है, साथ ही सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय मात्र परीक्षा केंद्र के रूप में चलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके कुछ बच्चे निजी-विद्यालयों में जाते हैं, परंतु वहाँ शुल्क अधिक होने के कारण गरीब बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। कुछ ही बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ पाते हैं। सरकारी विद्यालय लगभग

दोपहर भोजनकाल तक ही चलते हैं। ऐसी स्थिति में यह कह पाना मुश्किल है कि विद्यार्थी इन विद्यालयों में अध्ययन भी करते हैं या नहीं।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया वहां सामान्यतः यह पाया गया कि



अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग अभी भी खुले क्षेत्र में ही शौचालय के लिए जाते हैं। अंबेडकर गांव जहाँ सरकार ने शौचालय बनवाकर दिये हैं, वहां भी शौचालय अधिकतर प्रयोग में नहीं हैं। लोगों में शौचालयों के प्रति जागरूकता कम पायी गयी। कुछ शौचालय, अन्य गाँवों भांति उपले सहजकर रखने में प्रयोग होते दिखे। अगर लोगों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य की चर्चा करें तो यह पाया गया कि इस जिले में अभी भी गरीबी सर्वव्याप्त है। जिन गांव का सर्वेक्षण किया गया, वहां कच्चे और पक्के दोनों



प्रकार के घर पाये गये। कई स्थानों पर वर्गवार पुरवे पाए गए। सामान्य वर्ग के पुरवों की हालत अनुसूचित वर्ग के पुरवों की तुलना में अच्छी थी। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं। कुछ जगह कुएं भी खुदे हुए हैं और

आज भी लोग इनका पानी पीते हैं। इन क्षेत्रों में बिजली नाममात्र के लिए ही रहती है। यह जानकर हैरानी हुई कि लगभग सभी परिवार में मोबाइल फोन है, परंतु यह भी पाया गया कि अधिकांश संख्यामें घरों में टीवी

नहीं है। सुल्तानपुर जिले में यह देखा गया कि लड़कियां घर के काम के अतिरिक्त खेतों में काम भी करती हैं। बातचीत के दौरान यह पता चला कि शिक्षा हेतु लड़कियों को कम समय मिल पाता है, फिर भी लड़कियां गांवों में पढ़ रहीं हैं। अभिभावक अब लड़कियों की शिक्षा के लिए भी जागरूक हो रहे हैं; परंतु अभी भी लड़कों को शिक्षा में वरीयता देते हैं। गांव की लगभग सभी लड़कियां 8 वीं या 10वीं तक तो पढ़ लेती हैं लेकिन इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उनके गांव के आस पास कोई सरकारी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज नहीं है।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

सर्वेक्षण में 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चे सम्मिलित हुए। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 28.33 % लड़के तथा 71.66 % लड़कियां हैं। आँकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि:

- 41 % बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं, जबकि 27 % बच्चों के माता-पिता कृषि कार्य करते हैं, केवल 32% बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में पाये गए।
- सभी बच्चों के एक से अधिक भाई-बहन हैं और 62 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है।
- 10% बच्चों ने कक्षा पांच के बाद, 19 % बच्चों ने कक्षा 8 के बाद तथा 47% बच्चों ने 10 या 12 वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि 95 % अवसर मिलने पर पुनः पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानके विस्तार की वहाँ कितनी संभावनाएं हैं।
- 95 % बच्चों ने बताया उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं अर्थात् इन बच्चों के लिए वह शिक्षा उपयोगी होगी, जो रोजगारपरक हो।

- 50 % बच्चों ने पढाई बीच ने छोड़ने का कारण विद्यालय घर से दूर होना, 30% बच्चों ने माता-पिता के शुल्क न देने की क्षमता तथा 20% बच्चों ने माता-पिता की अनिच्छा बतायी।



उपयुक्त बिंदुओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है-

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा को द्वार-द्वार तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ऐसी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए जो रोजगार दे, सुलभ और सस्ती हो और बच्चों की रुचि क्षेत्रों से जुड़ी हो। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र के विकास की आवश्यकता है, जो इन बच्चों तक शिक्षा के पहुंच के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान प्रयासों को सफल बना सके।
- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो वह स्पष्ट होता है कि 65 % बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं सिलाई और कढ़ाई, 27 % बच्चों के प्राथमिकता ब्युटीशियन, 19 % बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर, 8 % बच्चों की प्राथमिकता मोबाइल ठीक करना और लगभग 3% बच्चों की प्राथमिकता इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सम्बन्धी काम सीखने की है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई-कढ़ाई, ब्युटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जैसे विषय इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.5. अमेठी जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

अमेठी जिले का निर्माण सुल्तानपुर और रायबरेली जिले की कुछ तहसीलों को मिलाकर किया गया, यह एक नया जिला है। यह जिला फैजाबाद मण्डल के अंतर्गत आता है। इस जिले में कुल चार तहसीलें, अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना और तिलोई हैं। जिले का प्रशासनिक नाम अमेठी है परंतु मुख्यालय गौरीगंज है। उपर्युक्त तहसीलों के अन्तर्गत विकासखंडों की कुल संख्या 13 है। इस जिले में गोमती नदी बहती है, जिसके कारण यहाँ की भूमि

अत्यंत उपजाऊ है। 2011 की जनगणना में इस जिले का ब्योरा नहीं है क्योंकि अमेठी जिले का गठन 2010 में किया गया था। जिले में कुल



2498 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में एन. आई. ओ. एस. का ना तो एक भी प्रत्यायित संस्थान (AIs) है और ना ही कोई प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान (AVIs)।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए:

अमेठी जिले में अमेठी, गौरीगंज, तिलोई तथा मुसाफिरखाना नाम की कुल 4 तहसीलें आती हैं। इस अध्ययन में उपर्युक्त चारों तहसीलों के सटवा, पीढ़ीबहादुरपुर, गुनिया मधूपुर, बेहटा, पूरे हरपाल सिंह बैस, नारा अधनपुर, छतरी, उखरेंमऊ, खादे का पुरवा तथा जानापुर नामक दस गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 16 पुरुषों व 34 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 18 बालकों व 42 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति तथा शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:



जिला अमेठी के अधिकतर गांवों में और गांवों से जुड़ी सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। कई जगहों पर इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि उनसे गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिले से गुजरने वाले राजमार्ग की हालत भी बहुत जगह खराब है। इससे यह समझा जा सकता है कि वहां के रहने वाले लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश गाँवों में 1-2 कि. मी. के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्थित है, परंतु अध्यापकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। कई विद्यालयों में केवल एक या दो ही अध्यापक हैं। इन विद्यालयों की स्थिति भी चिन्ताजनक है। जिला अमेठी में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज भी अपेक्षाकृत कम हैं।



ii. शैक्षिक स्थिति: जिला मुख्यालय पर उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी तथा सरकारी आंकड़ों (2014-15) के अनुसार जिले में 2498 विद्यालय हैं, जिनमें से 54 बिना शिक्षक के, 230 एक शिक्षक वाले तथा 543 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल

827 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। 466 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए और 283 विद्यालयों में बालकों लिए शौचालय काम नहीं कर रहा है। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1517 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे में यहाँ आधुनिक सूचना और सम्प्रेषण तकनीकी के युगमें तकनीकी आधारित शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ और तथ्य स्पष्ट होते हैं, वे इस प्रकार हैं:

- विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परन्तु उनमें अभी भी मूलभूत सुविधायों का अभाव है।
- 827 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु विद्यालयों में शिक्षा उचित प्रकार से नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनमें से कुछ के बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं। यह भी देखने में आया कि सरकारी विद्यालय लगभग दोपहर भोजन काल तक ही चलते हैं। ऐसी स्थिति में यह कह पाना मुश्किल है कि विद्यार्थी इन विद्यालयों में अध्ययन हेतु आयेंगे भी या नहीं।
- सरकारी तथा अनुदानित विद्यालयों की तुलना में गैर-अनुदानित विद्यालयों की संख्या बहुतायत में है।
- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या संतोषजनक नहीं है और कुछ विद्यालय तो अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं, उदाहरणार्थ: मुसाफिरखाना का राजकीय बालिका इन्टर कॉलेज (नीचे चित्र दिया गया है)



ऐसी स्थिति में यह सोचनीय है कि विद्यार्थी क्या ऐसे विद्यालयों में अध्ययन हेतु आयेंगे जो कभी भी गिर सकते हैं।

- सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा और जन-सामान्य के उन पर अविश्वास का लाभ उठा कर बहुत से निजी विद्यालय इन क्षेत्रों में खुल गए हैं, जो दूर देहात में भी “कान्वेंट” जैसे शब्दों को अपने नाम में जोड़ कर भोली-भाली जनता को अँग्रेजी शिक्षा का सपना दिखा कर लूट रहे हैं, जैसे कि लाखनबाबा कान्वेंट स्कूल या ऐसे ही अन्य छद्म विद्यालय।



अमेठी जिले की शिक्षा व्यवस्था को वहां की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की टिप्पणी से स्पष्ट समझा जा सकता है, जहाँ वह कहती हैं – “अमेठी, फैजाबाद से 25 साल पीछे है, मैंने अपने मायके में 20 वर्ष पहले BA किया था और मेरी सुसराल में शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण मैंने अपने बच्चे मायके छोड़े हुए हैं”।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:

जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया वहां सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग खुले क्षेत्र में ही शौचालय के लिए जाते हैं। लोगों में शौचालयों के प्रयोग



के प्रति जागरूकता कम पायी गयी। कुछ शौचालय उपले, लकड़ियाँ इत्यादि सहजकर रखने में प्रयोग होते दिखे।



अगर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा करें तो यह पाया गया कि इस जिले में अभी भी बहुत गरीबी है। जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया वहां कच्चे और पक्के, दोनों प्रकार के घर पाये गये। कई गांवों में तो अधिकतर घर कच्चे ही पाये गये। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग या तो सरकारी हैंडपम्प का प्रयोग

करते हैं या कई जगह कुएं भी खुदे हुए हैं और यहाँ के लोग इनका पानी पीते हैं। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अमेठी के कुछ गाँव में लोग अभी भी गोमती नदी का पानी पीते हैं। इन क्षेत्रों में बिजली औसतन 2-5 घंटे ही रहती है।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लगभग सभी परिवारों के पास मोबाइल फोन है परंतु यह भी पाया गया कि अधिकांश संख्या में घरों में टीवी नहीं है। अमेठी जिले में यह देखा गया कि लड़कियां घर के काम के अतिरिक्त गाय बकरी चराना, खेतों में काम करना आदि काम भी करती हैं।



बातचीत के दौरान यह पता चला कि गांवों में जो मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये, वे उपलब्ध नहीं हैं। अगर शिक्षा की बात की जाये तो यह पाया गया कि लड़कियां अब गांवों में भी पढ़ रहीं हैं और अभिभावक अब लड़कियों के लिए भी जागरूक हो गये हैं परंतु यदि वरीयता की बात कि जाए तो वह अब भी लड़कों के साथ है। गांव की लगभग सभी लड़कियां 5वीं-8वीं तक तो पढ़ लेती हैं, लेकिन इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती है क्योंकि उनके गांव के आस पास कोई माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज नहीं हैं।

सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि गोमती नदी के किनारे स्थित गांवों में आवागमन, शिक्षा और स्वास्थ्य साधनों की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है कई गांवों के बीच वास्तविक दूरी 4-5 कि.मी. ही है परंतु नदी पर पुल न होने के कारण उन्हें सड़क से 20-25 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित मुख्य जानकारियां सामने आयीं:



- सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 30 % लड़के तथा 70 % लड़कियां हैं।
- 65.33 % बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं, जबकि मात्र 28 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं। केवल 6.66 % बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में हैं।
- 89.33 % बच्चे दो से अधिक भाई-बहन हैं और 48 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 20% बच्चों ने कक्षा पांच तक, 36 % बच्चों ने कक्षा 8 तक तथा 44 % बच्चों ने 10 या 12 तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि 58 % बच्चे अवसर मिलने पर पुनः पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानके विस्तार की वहां कितनी संभावनाएं हैं।
- 72 % बच्चों ने बताया उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं अर्थात् 72 % बच्चों के लिए वह शिक्षा उपयोगी होगी, जो रोजगारपरक है।
- 46.66 % बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ने का कारण विद्यालय का घर से दूर होना बताया, 22.66 % बच्चों ने माता-पिता के शुल्क न देने की क्षमता तथा 16 % बच्चों ने माता-पिता की अनिच्छा को कारण बताया।

उपयुक्त बिंदुओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- यदि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बना ले और वहाँ के बच्चों की रुचि के अनुरूप रोजगारपरक, सुलभ और सस्ती शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करे तो शिक्षा को द्वार-द्वार तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के लिए असीम संभावनाएँ हैं। संस्थान को शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी और एक सशक्त निगरानी तंत्र का विकास करना होगा। निश्चय ही यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा क्योंकि यहाँ के लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नाम से भी परिचित नहीं हैं।
- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 42.66 % बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं सिलाई और कढ़ाई, 29.33 % बच्चों के प्राथमिकता ब्युटीशियन, 20 % बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर है। इसके साथ ही कुछ बच्चों ने ऑटो रिपेयरिंग और पेंटिंग में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की।
- इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई और कढ़ाई, ब्युटीशियन, कम्प्यूटर, ऑटो रिपेयरिंग आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.6. रायबरेली जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

रायबरेली उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक है, जो कि अवध क्षेत्र में आता है। यह जिला फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत आता है। इस जिले के अन्तर्गत रायबरेली सदर, डलमऊ, महाराजगंज, लालगंज, ऊंचाहार तथा सलोन नाम की कुल 6 तहसीलें आती हैं।

तहसीलवार विकासखंडों की कुल संख्या 15 है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या



34,04,004 है, जिसमें 17,53,344 पुरुष तथा 16,50,660 महिलाएँ हैं। यहाँ के जनगणना संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 2001 की तुलना में यहाँ लिंगानुपात में भारी गिरावट हुई है, जो 0-6 वर्ष आयु वर्ग में चिंतनीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 941 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत साक्षरता 69.04 % है, जबकि पुरुष साक्षरता 79.39% तथा स्त्री साक्षरता मात्र 58.06 % ही है। जिले में कुल 3539 विद्यालय हैं। यहाँ की 9.39 % जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में, जबकि 90.61% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 04 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 01 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

रायबरेली जिले में रायबरेली, डलमऊ, महाराजगंज, लालगंज, ऊंचाहार तथा सलोन कुल 6 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में रायबरेली (सदर), महाराजगंज के रूप में दो तहसीलों के पहाड़ाखेरा, सोहरा, नया पुरवा और अमरावां नामक 4 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को



पूरित करने के लिए कुल 30 पुरुषों व 20 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 06 बालकों व 54 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:

रायबरेली जिले के भ्रमण के दौरान यह देखने में आया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति तुलनात्मक रूप से ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों तथा



राज्यमार्गों की स्थिति संतोषजनक है, साथ ही अधिकांश गाँव भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जुड़े हैं। सड़कों की हालत तुलनात्मक रूप से निकट के जिले अमेठी से काफी-कुछ ठीक थी। सर्वेक्षण के दौरान गाँवों के अधिकांश घरों में शौचालय नहीं मिले। यह पाया गया कि अधिकांश गाँवों में 1-2 कि. मी. के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। जिला रायबरेली में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज उचित संख्या में हैं और लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता है।

ii. शैक्षिक स्थिति: सरकारी आंकड़ों के अनुसार (2014-15) रायबरेली में 3539 विद्यालय हैं, जिनमें से 29

बिना शिक्षक के, 489 एक शिक्षक वाले तथा 370 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 888 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1801 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ तकनीकी आधारित शिक्षा की संभावना नहीं है। उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ अन्य तथ्य भी स्पष्ट होते हैं जो निम्नलिखित है:-



- विद्यालयों की संख्या भले ही पर्याप्त हो परंतु वहाँ अभी भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- 888 से अधिक सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अकल्पनीय है। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय मात्र परीक्षा केंद्र के रूप में चलते हैं, जहाँ रोजमर्रा की पढ़ाई ना के बराबर होती है। दिन में मध्याह्न-भोजन के बाद लगभग अधिकांश विद्यालय बंद हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ज्यादातर घरों के बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं, परंतु वहाँ शुल्क अधिक होने के कारण गरीब बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। केवल वही आगे पढ़ पाते हैं, जो शुल्क अदा कर पाते हैं।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। अंबेडकर गांव जहाँ सरकार ने शौचालय बनवाकर दिये, वहाँ भी शौचालय अधिकतर प्रयोग में नहीं आते हैं। इसके कई तकनीकी कारण देखने में आए जैसे गड्ढे का छोटा होना, पानी का अभाव आदि। इस जिले में भी लोगों में शौचालयों के प्रयोग के प्रति जागरूकता कम पायी गयी।



गाँवों में परम्परागत रूप से जाति के आधार पर पुरवों/ टोलों की उपस्थिति देखी गयी। अनुसूचित जाति की बहुलता वाले पुरवों/ टोलों में गरीबी ज्यादा दिखी। जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के घर पाये गये। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं परंतु कई जगह उच्च वर्ग के घरों में निजी कुएँ भी खुदे हुए हैं और लोग इनका पानी पीते हैं। इन क्षेत्रों में बिजली औसतन 7-8 घंटे ही रहती है। अधिकांश लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, वो चाहे बहुत गरीब हों या अमीर। यद्यपि अधिकांश संख्या में घरों में टीवी नहीं है। अगर शिक्षा की बात की जाये तो यह पाया गया कि गाँवों की लगभग सभी लड़कियां 5वीं-8वीं तक तो पढ़ लेती हैं, लेकिन इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनके

गांव के आस पास कोई अच्छा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं हैं। अधिकांश परिवार बालिकाओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं करते।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 10% लड़के तथा 90% लड़कियाँ हैं। आकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि 22.72 % बच्चों के माता-पिता मज़दूरी करते हैं, जबकि 68.18 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं। केवल 9.09 % बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में पाये गए; शेष की अपनी दुकान या स्व-रोजगार है। चयनित सभी बच्चे दो से अधिक भाई-बहन वाले हैं और 59.09 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 18.17 % बच्चों ने कक्षा 5 तक तथा 45.45 % बच्चों ने 8 तक, 13.63% बच्चों ने 10 तक और 22.72% बच्चों ने 12 तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी बच्चे अवसर मिलने पर आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार की यहाँ कितनी संभावनाएँ हैं। 86.36 % बच्चों ने बताया उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं और स्वावलंबी होना चाहते हैं।

उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि-

- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि 77.27% बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकता सिलाई और कढ़ाई, 27.27 % बच्चों की प्राथमिकता ब्यूटीशियन तथा 4.54% बच्चों की प्राथमिकता मोबाइल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रिशियन सम्बन्धी कार्य करने की है।
- इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त विषयों में रोजगारपरक, सर्वसुलभ और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.7. फ़ैज़ाबाद जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

फ़ैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक है, जो पवित्र नगरी अयोध्या के निकट स्थित है। अयोध्या फ़ैज़ाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। यह फ़ैज़ाबाद मंडल का मण्डल मुख्यालय भी है। इस जिले के अन्तर्गत बिकापुर, रुदौली, फ़ैज़ाबाद, सोहावल तथा मिल्कीपुर के रूप में कुल 5 तहसीलें आती हैं। जिले में विकास खंडों की कुल संख्या 11 है। यहां से मुख्यतः सरयू नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 24,68,371 है, जिसमें 12,58,455 पुरुष तथा 12,09,916 महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार

लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 961 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत साक्षरता 70.63 % है जबकि पुरुष साक्षरता 80.21 % तथा स्त्री साक्षरता मात्र 60.72 % ही है। जिले में कुल 3742 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि



है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 02 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 02 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

फ़ैज़ाबाद जिले में बिकापुर, रुदौली, फ़ैज़ाबाद, सोहावल तथा मिल्कीपुर कुल 5 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में बिकापुर, फ़ैज़ाबाद (सदर) तथा मिल्कीपुर के रूप में तीन तहसीलों के कुसुम्हा, सोनखरी, भवानी, भीखू मिश्रा का पुरवा नामक 4 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 30 पुरुषों व 20 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 20 बालकों व 40 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

i. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:

फ़ैज़ाबाद जिले के भ्रमण के दौरान ये देखने में आया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति आस पास के जिलों से तुलनात्मक रूप से ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यमार्गों की स्थिति संतोषजनक है, साथ ही अधिकांश गाँव भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जुड़े हैं, परन्तु नदी (सरयू) के आस पास के गाँवों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गाँवों में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि

अधिकांश गाँवों में 1-2 कि. मी. के क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय स्थित है। जिला फ़ैज़ाबाद में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज तो उचित



संख्या में हैं ही और लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता भी है। चूंकि इस जिले में विश्वविद्यालय के साथ साथ कई अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इसलिए लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता भी दिखी।

ii. शैक्षिक स्थिति:

सरकारी आंकड़ों के अनुसार (2014-15) में फ़ैज़ाबाद में 3742 विद्यालय हैं, जिनमें से 4 बिना शिक्षक के, 53 एक शिक्षक वाले तथा 434 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 491 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। 191 विद्यालयों में शौचालय नहीं है जबकि 72 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1827 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इन विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा एक स्वप्न जैसा है।



उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ अन्य तथ्य भी स्पष्ट होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

- विद्यालयों की संख्या की तुलना में यहाँ अभी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- 491 सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं, ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु वहाँ रोजमर्रा की पढ़ाई नहीं होती। अधिकतर बच्चे केवल मध्याह्न भोजन के लिए आते हैं और भोजन करने के उपरांत अपने घर को चले जाते हैं और विद्यालय भी लगभग बंद हो जाते हैं।
- आम जनता सरकारी शिक्षा व्यवस्था से घोर निराशा में है। जो अभिभावक आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं वे अपने बच्चों को दूर या निकट के अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिला देते हैं। परंतु अधिकतर ग्रामीणों के बच्चे वहाँ के निकटतम सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ते हैं।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:

जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। जहाँ सरकार ने शौचालय बनवाकर दिये, वहाँ भी शौचालय अधिकतर प्रयोग में नहीं आते हैं।

इस जिले में भी गाँवों में परम्परागत रूप से जाति के आधार पर पुरवों/ टोलों की उपस्थिति देखी गयी। अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य सामान्य वर्ग की जातियों के पुरवों में भी समान रूप से गरीबी दिखी। जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ कच्चे और



पक्के दोनों प्रकार के घर पाये गये। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं परंतु कई जगह कुएँ भी खुदे हुए हैं जिनका उपयोग अभी भी होता है। इन क्षेत्रों में बिजली औसतन 6-7 घंटे ही रहती है। अधिकांश लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। परंतु यह भी देखा गया कि अधिकांश संख्या में घरों में टीवी नहीं है। अगर शिक्षा की बात की जाये तो यह पाया गया कि अभिभावक अब लड़कियों के लिए भी जागरूक हो गये हैं परंतु उच्च शिक्षा में वरीयता अब भी लड़कों के लिए ही है। गाँवों की लगभग सभी लड़कियाँ 8वीं-10वीं

तक तो पढ़ लेती हैं लेकिन इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनके गांव के आस पास कोई अच्छा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं हैं।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव

सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 33.33% लड़के तथा 66.66% लड़कियाँ हैं। आकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि 40.54 % बच्चों के माता-पिता मज़दूरी करते हैं, जबकि मात्र 27.02 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं। केवल 32.43 % बच्चों के माता-पिता किसी वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में पाये गए, शेष की अपनी दुकान या स्व-रोजगार है। सभी चयनित बच्चे दो से अधिक भाई-बहन वाले हैं और 43.24 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 24.32 % बच्चों ने कक्षा 8 तक, 10.81 % बच्चों ने 9 तक, 27.02 % बच्चों ने 10 तक तथा 37.83% ने 12 या उससे अधिक तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी बच्चे अवसर मिलने पर आगे पढ़ने के इच्छुक हैं। 94.59 % बच्चों ने बताया उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है और यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अपने केन्द्रों को स्थापित करके आसानी से कर सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है -

- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो वह स्पष्ट होता है कि 51.35% बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकता सिलाई और कढ़ाई, 5.40 % बच्चों की प्राथमिकता ब्यूटीशियन, 24.32 % बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर, 13.51% बच्चों की प्राथमिकता इलेक्ट्रिशियन तथा 8.10% बच्चों की प्राथमिकता मोबाइल ठीक करने इत्यादि की है।
- इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को इन विषयों में व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.8. अम्बेडकरनगर जिला

1. जिले का सामान्य परिचय

अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश के नव निर्मित जिलों में से एक है। यह जिला फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत आता है। इस जिले के अन्तर्गत बिहिटी, टांडा, अकबरपुर, अल्लापुर, तथा जलालपुर कुल 5 तहसीलें आती हैं। इन तहसीलों में विकासखण्डों की कुल संख्या 09 है। यह जिला घाघरा नदी के निकट स्थित है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की भूमि उपजाऊ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 23,98,709 है, जिसमें 12,14,225 पुरुष तथा 11,84,484 महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 976 स्त्रियाँ है। यहाँ की औसत साक्षरता 74.37 % है, जबकि पुरुष साक्षरता 83.95% तथा स्त्री साक्षरता मात्र 64.82 % ही है। जिले में कुल 3566 विद्यालय हैं। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में एन. आई. ओ. एस. के 05 प्रत्यायित संस्था (AIs) तथा 03 प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था (AVIs) हैं।

2. जिले के उन स्थानों व लोगों का विवरण, जहाँ से व जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए गए

अंबेडकरनगर जिले में बिहिटी, टांडा, अकबरपुर, अल्लापुर, तथा जलालपुर कुल 5 तहसीलें आती हैं, जिनमें से इस अध्ययन में बिहिटी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर चार तहसीलों के अरई, रोशनपुर मजरा, केवटही,



ब्राह्मिनपुर, कुसुमा सागरा नामक 6 गाँवों को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन के दौरान चयनित गाँवों में अवलोकन अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 30 पुरुषों व 20 स्त्रियों से बातचीत की गयी तथा साक्षात्कार अनुसूची को पूरित करने के लिए कुल 09 बालकों व 51 बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

3. अवलोकन अनुसूची के आधार पर जिले की आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

- i. **आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से स्थिति:** अंबेडकरनगर जिले के भ्रमण के दौरान ये देखने में आया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति तुलनात्मक रूप से ठीक है। राष्ट्रीय

राजमार्गों तथा राज्यमार्गों की स्थिति संतोषजनक है; साथ ही अधिकांश गाँव भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जुड़े हैं परन्तु नदी के आस पास के गाँवों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गाँवों के अधिकांश घरों में शौचालय



नहीं हैं। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश गाँवों में 1-2 कि. मी. के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्थित है। जिला अंबेडकरनगर में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचित संख्या में हैं। परंतु इंटर और डिग्री कॉलेजों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। लोगों में शिक्षा प्राप्त करने को लेकर जागरूकता है परंतु जिला अंबेडकरनगर के गावों में अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी है।

- ii. **शैक्षिक स्थिति:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार (2014-15) में अंबेडकरनगर में 3566 विद्यालय हैं जिनमें से 104 एक शिक्षक वाले तथा 376 दो शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इस प्रकार कुल 480 विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं।

आंकड़ों के अनुसार 06 विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं और 03 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं हैं। एक



और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1854 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है।

उपर्युक्त आंकड़ों से कुछ अन्य तथ्य भी स्पष्ट होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

- अन्य जिलों के विद्यालयों की तुलना में यहाँ अभी भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- 480 से अधिक सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3 से कम अध्यापक हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं की जा सकती। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है परंतु सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में रोजमर्रा की पढ़ाई सिर्फ दिखावा मात्र है। यहाँ भी ग्रामीणों ने बताया की कुछ सुविधा सम्पन्न परिवार के बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं परंतु शुल्क अधिक होने के कारण गरीब बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ाई हेतु नहीं जा पाते।

iii. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: जिन गांवों

का सर्वेक्षण किया गया वहाँ सामान्यतः यह पाया गया कि अभी भी बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय हैं। लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। अन्य जिलों की भांति यहाँ भी जो अंबेडकर गांव हैं, जहाँ सरकार ने शौचालय बनवाकर दिये, लेकिन अधिकतर प्रयोग में नहीं



आते हैं। ये शौचालय उपले, लकड़ियाँ रखने के कार्य में प्रयुक्त होते दिखे या फिर बंद दिखाई दिये। कुछ पुराने

कुएँ भी देखे गए जो प्रायः प्रचलन में नहीं हैं। गाँवों में परम्परागत रूप से जाति के आधार पर पुरवों/ टोलों की उपस्थिति देखी गयी। यह भिन्नता उनकी आर्थिक स्थिति व रहन-सहन में भी दिखाई दी। सर्वेक्षण के दौरान कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के घर पाये गये। कुछ पुरवों में तो अधिकतर घर कच्चे ही पाये गये जो



मूलतः अनुसूचित जाति वर्ग के थे। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए अधिकतर लोग हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में बिजली औसतन 6-7 घंटे ही रहती है। अधिकांश लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं परंतु

यह भी पाया गया कि अधिकांश संख्या में घरों में टीवी नहीं है। यह भी पता चला कि गाँवों की अधिकांश लड़कियां अब पढ़ाई कर रही हैं। अभिभावक भी इस संबंध में जागरूक दिखे। यह जागरूकता अपेक्षाकृत गरीब परिवार में भी देखी गयी। गाँवों की लगभग सभी लड़कियां 8वीं-10वीं तक तो पढ़ लेती हैं, लेकिन इसके पश्चात वह नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनके गाँव के आस पास कोई सरकारी या अच्छा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं हैं।

4. साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति; वहाँ के बच्चों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्त की गयीं रुचियाँ; उन बच्चों तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच सम्बन्धी स्थिति व जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को सुझाव:-

सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चों का आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बच्चों में 15% लड़के तथा 85% लड़कियां हैं। आकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि 44.18 % बच्चों के माता-पिता मज़दूरी करते हैं, जबकि 41.86 % बच्चों के माता पिता कृषि कार्य करते हैं, केवल 13.95 % बच्चों के माता-पिता किसी

वैतनिक रोजगार या सरकारी नौकरी में पाये गए, शेष की अपनी दुकान या स्व-रोजगार है। चयनित सभी बच्चे दो से अधिक भाई-बहन वाले हैं और 41.86 % परिवारों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 18.60 % बच्चों ने



कक्षा 8 तक तथा 41.86 % बच्चों ने 10 तक तथा 39.53% बच्चों ने 12 तक की पढ़ाई की है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी चयनित बच्चे अवसर मिलने पर आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के विस्तार की वहाँ कितनी संभावनाएँ हैं। सभी बच्चों ने बताया उनके आगे पढ़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि वे पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं से निष्कर्ष

निकाले जा सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा को द्वार-द्वार तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं:

- बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 51.16% बच्चों की व्यावसायिक प्राथमिकता सिलाई और कढ़ाई, 13.95 % बच्चों की प्राथमिकता ब्यूटीशियन, 32.55 % बच्चों की प्राथमिकता कम्प्यूटर, 11.62% बच्चों की प्राथमिकता मोबाइल रिपेयरिंग तथा 6.97% की प्राथमिकता मेडिकल संबंधी प्रशिक्षण है।
- इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को इन विषयों में इस जिले में व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

नोट: अध्ययन हेतु चयनित समस्त जिलों में शिक्षा की स्थिति के संबंध में प्रस्तुत आंकड़े

http://www.dise.in/Dise2001/Reports/2014-15/Report_UP2014-15.pdf से लिए गए हैं।

9.0 अध्ययन के निष्कर्ष

जिलावार आंकड़ों के विश्लेषण और अध्ययन के उपरांत निष्कर्षों को निम्नलिखित दो शीर्षकों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है:

9.1. जिलों की भौतिक सुविधाओं, शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक चित्रण

9.2. प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष

9.1. जिलों की भौतिक सुविधाओं, शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक चित्रण

क्र. सं.	जिला	जनसंख्या			लिंगानुपात (पुरुष/महिला)	साक्षरता (%)			कुल विद्यालय	कुल NIOS के केंद्र	
		पुरुष	महिला	कुल		पुरुष	महिला	कुल		AIIs	AVIs
1.	बलिया	16,67,557	15,56,085	32,23,642	1000/933	85.91	61.72	73.82	3,841	2	2
2.	देवरिया	15,39,608	15,59,029	30,98,637	1000/1013	86.07	61.34	73.53	3,957	2	1
3.	गोरखपुर	22,81,763	21,54,512	44,36,275	1000/944	84.38	61.54	73.25	4,521	2	5
4.	सुल्तानपुर	19,16,297	18,74,625	37,90,922	1000/978	81.99	60.17	71.14	3,467	3	3
5.	अमेठी	नवसृजित जिला, जो 2010 में अस्तित्व में आया, होने के कारण जिले से संबंधित आंकड़े जनसंख्या संबंधी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं।						2,498	0	0	
6.	रायबरेली	17,53,344	16,50,660	34,04,004	1000/941	79.39	58.06	69.04	3,539	4	1
7.	फैजाबाद	12,58,455	12,09,916	24,68,371	1000/961	80.21	60.72	70.63	3,742	2	2
8.	अम्बेडकरनगर	12,14,225	11,84,484	23,98,709	1000/976	83.95	64.82	74.37	3,566	5	3

चयनित जिलों की जनसंख्या एवं साक्षरता के तुलनात्मक आंकड़े

9.1.1. आवश्यक भौतिक सुविधाओं व उससे संबंधित सेवाओं की दृष्टि से सभी जिलों की स्थितियों की विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के आठ जिलों फ़ैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, बलिया एवं देवरिया का चयन किया था। इनमें से गोरखपुर और फ़ैजाबाद जिला मुख्यालय के साथ साथ मण्डल मुख्यालय भी हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पुराना मण्डल है और फ़ैजाबाद नवोदित। इसी प्रकार से फ़ैजाबाद,

सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, बलिया एवं देवरिया उत्तर प्रदेश के पुराने जिले हैं, जो कि पर्याप्त सशक्त माने जाते हैं। अमेठी और अम्बेडकरनगर नवोदित जिले हैं, जो पड़ोस के जिलों में से कुछ तहसीलों को मिला कर निर्मित किए गए हैं। ये आठ जिले आठ संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फैजाबाद मण्डल कार्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकटवर्ती जिले फैजाबाद में स्थित है। गोरखपुर मण्डल कार्यालय हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित गोरखपुर जिले में आता है। इसी प्रकार से फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, बलिया एवं देवरिया जिलों के मुख्यालय अपने नाम के स्थानों (तहसीलों) में ही स्थित हैं, जबकि अम्बेडकरनगर का मुख्यालय अकबरपुर तहसील में स्थित है और अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज तहसील में स्थित है यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि अमेठी जिला ना होने की अवस्था में भी प्रारम्भ से ही संसदीय क्षेत्र रहा है। बलिया और देवरिया ये दोनों जिले बिहार की सीमा पर स्थित हैं; वहीं गोरखपुर नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार इन जिलों पर बिहार और नेपाल के संबंधों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुहाने पर स्थित है इसलिए इस जिले पर राजधानी का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इन जिलों से राष्ट्रीय राजमार्ग भी होकर गुजरते हैं। राज्यमार्गों की उपलब्धता भी पर्याप्त है। इसके बाद भी इन जिलों का अन्य पक्षों से संबंधित भौतिक विकास जितना हेमा चाहिए था, उतना नहीं हो सका। यद्यपि इन जिलों में केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक प्रतिष्ठान स्थापित हैं, फिर भी भौतिक तथा आधारभूत संरचना के विकास का अभाव चिंतनीय है। एक ओर जहाँ शहरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखता है, वहीं गाँवों में तो इनकी उपलब्धता ना के बराबर है। इन स्थानों में सड़कों की स्थिति या तो बहुत बुरी है या कई क्षेत्रों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा ही नहीं गया है। अमेठी जिले में गोमती नदी प्रतिवर्ष अनेक सीमावर्ती गाँवों की भूमि और सड़क को अपने प्रवाह से काट देती है। नदियों पर पुल के अभाव के कारण भी शहरों तक पहुँच मुश्किल है। बरसाती दिनों में यह स्थिति बद से बदतर हो जाती है। गाँवों में प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों से वार्तालाप के दौरान ये बातें ध्यान में आयीं कि अनेक परिवारों ने अपने बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर छोड़े हुए हैं, जिससे उनके बच्चे एक अच्छे मूलभूत सुविधाओं वाले जीवन को प्राप्त कर सकें। नागरिकों ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र ने देश की राजनीति की दृष्टि से भी भारत की संसद में अनेक यशस्वी नेताओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन कर भेजा है, जैसे स्वर्गीय फिरोज गाँधी, स्वर्गीय इंदिरा गाँधी, स्वर्गीय राजीव गाँधी, स्वर्गीय संजय गाँधी एवं स्वर्गीय चन्द्रशेखर। इनमें से तीन ने तो देश के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। साथ ही श्रीमती सोनिया गाँधी,

कैप्टन सतीश शर्मा, श्री राहुल गाँधी, डॉ० संजय सिंह, श्री वरुण गाँधी एवं योगी आदित्यनाथ, आदि वर्तमान में इस क्षेत्र के प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का जो द्रुतगामी विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व होने के उपरान्त भी यह क्षेत्र आज भी अपने विकास की बाट जोह रहा है तथा अपने पिछड़ेपन के कारणों को दूँढ़ रहा है, जो कि समस्त व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इनमें से अमेठी जिले में तो कई स्थानीय निवासियों ने यहाँ तक कहा कि उन्हें आज भी नदी और कुओं का जल पीना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने सर्वेक्षण दल को यह भी बताया कि सड़कों की जो खराब हालत आप देख रहे हैं वह बरसात में भयावह हो जाती है, पानी भरे गड्ढों से युक्त सड़कों से शहर पहुँच पाना अत्यंत मुश्किल होता है और ऐसे में किसी बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति का समय से शहर पहुँच पाना बहुत कष्टप्रद होता है।

9.1.2. शैक्षिक स्थिति की दृष्टि से सभी जिलों की स्थितियों की विवेचना

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि शोध हेतु चयनित सभी जिले बहुत पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। इन आठों जिलों में दो विश्वविद्यालय एक फैजाबाद में तथा एक गोरखपुर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज भी विद्यमान हैं। हाल के वर्षों में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की घोषणा की गयी है। यद्यपि इन क्षेत्रों में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय हैं तथापि इस क्षेत्र की शैक्षिक अवस्था बहुत चिंतनीय है। संपूर्ण देश में सर्वशिक्षा अभियान डेढ़ दशक से चल रहा है और 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' भी विगत कई वर्षों से माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी 2010 से प्रत्येक 8 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक तीन किलोमीटर पर एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना अनिवार्य है। साथ ही 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्रत्येक पांच किलोमीटर पर एक माध्यमिक विद्यालय तथा प्रत्येक सात किलोमीटर पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की योजना है। लेकिन, सर्वेक्षण दल ने जब इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो पाया कि या तो विद्यालय योजना के अनुसार हैं ही नहीं, यदि हैं तो वे बंद हैं या उनकी दशा अवर्णनीय है। उच्च शिक्षा की भी यही दशा है। सर्वाधिक आश्चर्य का विषय यह है कि कुछ स्थानों पर विद्यार्थी मध्यान भोजन एवं छात्रवृत्ति के लिए सरकारी विद्यालयों में पंजीकृत तो हैं किन्तु अध्ययन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में करते हैं,

जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में पंजीकरणकी संख्या में एवं वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या में भिन्नता पायी जाती है क्योंकि एक ही विद्यार्थी दो संस्थाओं में पंजीकृत होता है।

राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ, जो व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से सक्रिय हैं उनका भी परिचय व तत्सम्बन्धी सुविधा नागरिकों तक नहीं पहुँच पा रही है। यद्यपि कुछ केन्द्रीय विद्यालय इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं तथापि इनकी पहुँच ग्रामीण समुदाय तक नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा के दृष्टि से भी कोई कारगर कदम इस क्षेत्र में नहीं उठाये गए हैं। फैजाबाद, गोरखपुर, बलिया और रायबरेली के अतिरिक्त अन्य तीनों जिले देवरिया, अमेठी तथा अम्बेडकर नगर की दशा बहुत सोचनीय है। इन तीनों में भी सर्वाधिक चिंता का विषय अमेठी का शैक्षिक परिदृश्य है। इस क्षेत्र ने लम्बे समय तक देश की संसद में शीर्ष नेतृत्व को स्थान प्रदान किया है फिर भी इस क्षेत्र का शैक्षिक विकास उनकी भावना के अनुरूप परिलक्षित नहीं होता है। बालिकाओं के लिए दूर-दूर तक विद्यालयों का अभाव दिखता है, वहीं आवागमन के साधन भी ना के बराबर हैं। अमेठी में शिक्षा की स्थिति के विषय में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में रखना पड़ता है। कुछ गाँवों से व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा बालिकाएँ विद्यालय जाती जरूर हैं, लेकिन व्यवस्थित मार्ग के अभाव में उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में आज भी बालिकाओं के द्वारा पशुओं की देखभाल तथा खेती व मज़दूरी सम्बन्धी कार्य करना आम बात है। इस प्रकार के अनेक विषय इस क्षेत्र के विकास पर बड़े प्रश्न खड़ा करते हैं।

9.1.3. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की दृष्टि से सभी जिलों की स्थितियों की विवेचना

इस क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षकों के सम्मुख यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र (देवरिया, अमेठी तथा अम्बेडकर नगर; विशेष रूप से अमेठी) के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए शैक्षिक परिदृश्य एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति जिम्मेदार हैं। विगत कई दशकों के अनुभवों के आधार पर क्षेत्र के नागरिकों से वार्ता करने के उपरान्त यह ध्यान में आया कि इस क्षेत्र का भावनात्मक शोषण ज्यादा हुआ है, चाहे वह राजनेताओं ने किया हो या धार्मिक लोगों ने। जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वह भला आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से दरिद्र कैसे हो सकता है? यद्यपि इस क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रियाशील हैं किन्तु इनकी सक्रियता ने यहाँ की सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्य बदलने में कोई भूमिका निर्वहन नहीं की है; क्योंकि जो सार्वजनिक इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की गयीं उनका संबंध यहाँ के जन और जमीन से कम, राजनीति से अधिक रहा है; इसलिए ना तो यहाँ पर ये इकाइयाँ ही बन पायीं और ना ही जनता। अन्य जिलों

की तुलना अमेठी से करने पर यह स्पष्ट होता है कि अन्य जिलों के विकास में राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रबल हाथ रहा है। उदाहरण के लिए हम बलिया, अमेठी और गोरखपुर की तुलना कर सकते हैं। अमेठी में 11 बार एक ही परिवार से संबंधित व्यक्ति भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करते रहे जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी से संबंधित थे; फिर भी, विकास के सभी आयामों पर यह क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है; वहीं दूसरी ओर गोरखपुर और बलिया का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो भारतीय संसद में लम्बे समय तक तो रहे किन्तु उनके दल शासन का हिस्सा कम समय तक रहा फिर भी उन क्षेत्रों का विकास अमेठी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। इन क्षेत्रों की जनता विकास के दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निर्वहन करती है। सर्वेक्षण के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ कि विकास को लेकर सर्वाधिक प्रश्न इन क्षेत्रों से ही आए। स्वाभाविक ही है कि यदि समाज प्रश्न करता है तो समाधान प्राप्ति का विकल्प उसके पास होता है। लेकिन जो समाज प्रश्न नहीं करता, वह समाधान का कभी हिस्सा भी नहीं होता। अमेठी क्षेत्र की जनता को प्रश्नों के प्रति जागरूक करने में वहाँ का नेतृत्व असफल रहा है इसलिए समाधान भी नहीं बन पाएँ हैं। शिक्षा जो आलोचनात्मक चेतना विकसित करती है तथा मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करती है (*सा विद्या या विमुक्तये*), उस शिक्षा के अभाव में इस पिछड़े क्षेत्र में ना तो विकास को लेकर नेतृत्व से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और ना ही अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी से मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त हो पा रहा है। सर्वेक्षण दल ने जब अमेठी के महिला प्रधानों से बात करने का प्रयास किया तो वे उच्च जाति वर्ग से होते हुए भी सामाजिक रूढ़ियों के कारण बात करने के लिए सामने नहीं आयीं। दल से बात करने के लिए प्रधान पति तथा उनके परिवार के लोग ही सामने आये, वहीं बलिया जिले में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिला प्रधानों ने भी सर्वेक्षण दल के समक्ष खुलकर अपनी बात रखी। इस प्रकार के उदाहरणों से अमेठी में सामाजिक पिछड़ापन स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा था। रोजगार के अवसरों के अभाव तथा सरकारी योजनाओं तक आम जन की पहुँच के अभाव में अमेठी जिले की आर्थिक दशा भी अन्य जिलों की तुलना में बदहाल दिखी।

9.2. प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष

प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्यों के क्रम में निष्कर्षों को व्यवस्थित करने पर उन्हें निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है:

- विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कार्यक्रम हेतु **मुख्य लक्षित समूह बालिकाएँ होनी चाहिए** क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में बालक तो 12वीं तक की शिक्षा के अवसरों का लाभ ले पा रहे हैं परंतु बालिकाएँ विद्यालय दूर होने, माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने, जल्दी विवाह होने आदि के कारण माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक से वंचित रह जा रही हैं। बहुत से माता-पिता बालिकाओं को बड़े होने के बाद अकेले दूर विद्यालय नहीं भेजना चाहते इसलिए भी वे शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जा रही हैं। इन क्षेत्रों में बालक व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए मुख्य लक्षित समूहके रूप में पाये गए।

- यदि बालिकाओं की शैक्षिक तथा व्यावसायिक अभिरुचियों की बात की जाए तो अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश बालिकाएँ **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ कर देख रहीं हैं**, अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ कर देना चाहिए। यदि बालिकाओं की व्यावसायिक अभिरुचियों पर दृष्टि डाली जाए जो अधिकांश बालिकाओं ने सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटीशियन तथा कुछ ने कम्प्यूटर तथा अध्यापन के प्रति अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की है। कुछ एक स्थानों पर बालिकाओं ने नर्सिंग जैसे विषयों में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

बालकों में व्यावसायिक क्षेत्रों को लेकर रुचि देखी गयी और वे व्यावसायिक कार्यक्रमों में प्रवेश को लेकर अधिक उत्साहित थे। बालकों ने कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोटर-मेकेनिक, पैरामेडिकल आदि क्षेत्रों में अपनी रुचि प्रदर्शित की।

- जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) की पहुँच तथा विस्तार के अवसरों का प्रश्न है। अध्ययन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की पहुँच वहाँ नहीं के बराबर है। जन सामान्य ने इस संस्था का नाम भी नहीं सुना है और

उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्य शिक्षा के साधनों की सीमित उपस्थिति और दूरस्थ गाँव तक पहुँच न होने के कारण वहाँ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के लिए विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। न केवल पारंपरिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कार्यक्रमों वरन व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी विकास के अच्छे अवसर उपस्थित हैं, परंतु इसके लिए एक विशिष्ट कार्य योजना की आवश्यकता है।

अध्ययन के द्वितीयक उद्देश्य के अनुसार इस शोध के निष्कर्षों को निम्न रूप से देखा जा सकता है:

- पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संबंधित शोधके उपरांत एक बात तो स्पष्ट है की ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संरचना कमोवेश एक जैसे ही है। सभी जिलों में जाति प्रथा और सामंतवादी सोच अभी भी कायम हैं। उच्च जतियों तक ही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। सामाजिक भेदभाव भी प्रच्छन्न रूप में दिखाई देता है। 'बाबू साहब' जैसे विशेषण आज भी सामान्य रूप से प्रचलन में हैं। पिछड़ी और अनुसूचित जतियों के बाहुल्य वाले गाँव की स्थिति चिंतनीय है केवल उन गाँव में थोड़ा बहुत आधारभूत ढांचा विकसित है जो कभी अंबेडकर गाँव रहे हैं। ऐसे गाँवों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यही हाल उन गाँवों का भी है, जो नदी किनारे स्थित हैं और जहाँ निषाद या अन्य पिछड़ी जातियाँ निवास करती हैं। ऐसे कुछ गाँवों तक तो कोई सुलभ संपर्क मार्ग भी नहीं है। इस आधार पर अध्ययन में सम्मिलित 8 जिलों में अम्बेडकरनगर, देवरिया और अमेठी सबसे पिछड़े जिले पाये गए हैं। अमेठी जिले में तो कुछ लोग आज भी गोमती नदी का पानी पीते हैं और वहाँ तक सीधे जाने के लिए नदी पर कोई पुल भी नहीं है। अतः वहाँ पहुँचने के लिए कई किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ न तो शिक्षा के साधन हैं और न ही स्वास्थ्य केंद्र।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों के 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जिन बालक-बालिकाओं से आंकड़े एकत्र किए गए, उनमें से अधिकांश के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की है। बहुत से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ने का कारण माता-पिता का विद्यालय को शुल्क न दे पाना या पढ़ाई के अन्य खर्च न उठा पाना बताया। आज भी वे मिट्टी के बने कच्चे घरों में रहते हैं। उनके परिवार में भाई बहनों की संख्या अधिक है। अधिकांश के माता-पिता मजदूरी करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं परंतु उन सब में शिक्षा के प्रति उत्साह और ललक देखी गयी।

- एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है की इतनी गरीबी के बाद भी **सभी के पास मोबाइल फोन है** परंतु खाना आज भी चूल्हे पर ही बनता है और घरों में शौचालय नहीं हैं। यह भी देखा गया कि **कुछ सम्पन्न परिवारों में घरों में ट्रेक्टर, कार आदि भी है और पक्के मकान भी हैं पर शौचालय नहीं हैं।**
- कई गाँवों में बच्चे सरकारी विद्यालयों के साथ साथ आस-पास के निजी विद्यालयों में भी नामांकित हैं। माता-पिता ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती; वहाँ एक-या दो अध्यापक होते हैं जो इधर-उधर सरकारी कागजातों को भरने के काम में ही दौड़ते-भागते रहते हैं और शिक्षा मित्र का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन बनवाने में निकल जाता है। भोजन वितरण के बाद छुट्टी हो जाती है। **बड़े गाँव में कान्वेंट स्कूल जैसे छद्म नाम वाले प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, जहाँ 100-200 रुपये प्रति माह के शुल्क पर बच्चे पढ़ने जाते हैं परंतु ये देखा गया कि ऐसे विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से बहुत अधिक है और माता-पिता ऐसे विद्यालयों के दूर होने के कारण लड़कियों को वहाँ नहीं भेज पाते। एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था से आम-जन का भरोसा उठ चुका है।**
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताएँ लगभग एक जैसी हैं। जहाँ बालिकाओं को **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा** के साथ साथ **रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा** की भी आवश्यकता है, वहीं बालकों को **रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा** देने की आवश्यकता है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों की 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है और बहुत से व्यवसायों के विषय में वो जानते भी नहीं हैं। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ आईटीआई में मिलने वाली ट्रेनिंग या कम्प्यूटर ट्रेनिंग तक ही सीमित है। बालिकाओं की व्यावसायिक अभिरुचि **सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर तथा अध्यापन** में है। कुछ बालिकाओं ने नर्सिंग जैसे विषयों में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है। बालकों ने **कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोटर-मेकेनिक, पैरामेडिकल** आदि क्षेत्रों में अपनी रुचि प्रदर्शित की।

10 . राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान हेतु सुझाव

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) के माध्यम से लक्षित समूह की शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानको पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान स्थापित करने और जन सामान्य तक अपनी पहुँच बनाने के लिए उचित स्थानीय प्रचार तंत्र का सहारा लेना चाहिए और सुचारु रूप से एक प्रचार अभियान चलाना चाहिए।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानद्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जो देवरिया, अमेठी या अंबेडकरनगर जैसे पिछड़े जिले में हो।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानको अपनी पारंपरिक पद्धति से इतर कुछ नया करने की आवश्यकता है क्योंकि गाँव-गाँव तक प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने होंगे और इसके लिए शहरी क्षेत्रों में स्थित अध्ययन केंद्र की व्यवस्था बहुत तर्क संगत प्रतीत नहीं होती।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को गाँव-गाँव में प्रवेश हेतु बालक बालिकाओं को जागरूक करने, उनका प्रवेश सुनिश्चित करने तथा उन तक अधिगम सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। साथ ही परामर्श सत्रों को अध्ययन केन्द्रों पर आयोजित करने के स्थान पर रेडियो या टेलिविजन या मोबाइल विडियो के रूप में अथवा यदि संभव हो तो सचल विडियो वाहन के माध्यम से ग्राम-पंचायत केन्द्रों पर आयोजित करना चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि संभव हो तो आवासीय व्यवस्था में 15-21 दिनों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएँ।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को अपने “फ़ेल विद्यार्थियों को पास कराने वाले बोर्ड” की नकारात्मक छवि तोड़ने का प्रयास करना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ कराने वाली संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने हेतु रणनीति तैयार करनी चाहिए।
- उपर्युक्त के संदर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्ययोजना बनाकर उसे “परियोजना” के रूप में मुख्यालय की निगरानी में संचालित करने और समय-समय पर उसके आंतरिक और बाह्य मूल्यांकनकी व्यवस्था करने का कार्य किया जा सकता है।